RNI No. : TNHIN/2013/52520 ▪ वर्ष - 14 ▪ अंक - 6 ▪ पृष्ठ - 8 ▪ रु. 5/- चेन्नई » मंगलवार » 28-07-2026 ▪ www.dakshinbharat.com ▪ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

4 दिया कुमारी ने मारवाड़ में विकास कार्यों का किया शिलान्यास

6 परिवार परम्परा एवं बिखरते रिश्ते पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

7 अब मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं : सानवी तलवार

फर्स्ट टेक

इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया की ओर से दागे ड्रोन मार गिराए : सऊदी अरब

काहिरा/एपी। सऊदी अरब ने कहा है कि उसने ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया द्वारा दागे गए ड्रोन मार गिराये हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय की ओर से सोमवार को सोशल मीडिया पर यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान ने कई हफ्तों से जारी तनाव और हमलों के बाद सप्ताहांत में अपने हमले रोक दिए थे। बयान में कहा गया है कि इन ड्रोन का निशाना पूर्वी सऊदी अरब स्थित पेट्रोलियम प्रतिष्ठान और राजधानी रियाद थे।

बेंगलूरु में व्यक्ति ने मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की

बेंगलूरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु में सोमवार को हुस्कुर रोड मेट्रो स्टेशन पर चलती ट्रेन के सामने एक व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की वजह से येलो लाइन पर सेवाएं संक्षिप्त समय के लिए बाधित रहीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। बेंगलूरु मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शाम करीब साढ़े पांच बजे घटी।

अबतक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल

नई दिल्ली/भाषा। आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए अबतक चार करोड़ आयकर रिटर्न भरे गये हैं। विभाग ने करदाताओं से 31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले अपना रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। विभाग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर करदाताओं से 31 जुलाई से पहले आयकर रिटर्न एक (सहज) और दो भरने को कहा है। आईटीआर-1 (सहज) एक सरल फॉर्म है, जिसे छोटे और मध्यम आय वर्ग के बड़ी संख्या में करदाताओं के लिए तैयार किया गया है।

बालों में तिरंगा, आंखों में आंसू : मीराबाई ने भारत को दी स्वर्णिम सौगात

ग्लास्गो/भाषा। मीराबाई चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में जीत गया स्वर्ण पदक देशभक्ति से ओतप्रोत था। तीन बार की चैंपियन मीराबाई ने रविवार को जब भारोत्तोलन खेलों में मंच पर कदम रखा, तो उन्होंने तिरंगे रिबन से बनी तितली के आकार की हेयर क्लिप पहनी हुई थी। यह देश की प्रति उनका सम्मान था, जिसे गौरवान्वित करने के लिए वह प्रतिबद्ध थी। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के बाद मीराबाई ने पीटीआई से कहा, ''मैं भारत के लिए कुछ करना चाहती थी, इसलिए मैंने कल रात भारतीय ध्वज के रंगों वाले रिबन से ये तितली की तरह के क्लिप बनाए।''

सूर्यास्त 28-07-2026 6:37 बजे	सूर्योदय 29-07-2026 5:55 बजे
BSE 76,835.78 (+776.01)	NSE 23,995.95 (+228.50)
सोना 15,022 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	चांदी 240,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

आरक्षण पर बोलो

किसको आरक्षण मिले यहां,
हो कर तटस्थ खुल कर बोलो।
कब तक आरक्षण मिले कहां,
अब न्याय तुला पर सच तोलो।
आरक्षण कितना मिले किसे,
वंचित के मूल्यों को मोलो।
आरक्षण की परिभाषा पर,
सब नेता अपने मुंह खोलो।।

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई मुद्दे पर हंगामा

चार बार के स्थगन के बाद रास दिन भर के लिए स्थगित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक सोमवार को चार बार के स्थगन के बाद शाम पांच बज कर पंद्रह मिनट पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और अन्य विधायी कामकाज नहीं हो पाया। चार बार के स्थगन के बाद शाम सवा पांच बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन

हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन हम चाहते हैं कि गृह मंत्री सदन में आएं और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें।

रीजीजू ने कहा कि ''विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी। लेकिन अब इस पर आप चर्चा नहीं कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा ''नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सदन में मौजूद हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइये जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जा कर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन यहां आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे।'' खरगे ने कहा ''हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन हम चाहते हैं कि गृह मंत्री सदन में आएं और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें।'' हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ और नीट प्रश्नपत्र लीक से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पिछले सप्ताह एक भी दिन सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाए। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक 2026 उच्च सदन में पिछले सप्ताह शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जायेगा और इसके लिए तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। आज इस विधेयक पर सदन में चर्चा होनी थी।

गृह मंत्री को सदन में बयान देना होगा और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी : खरगे

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बयान देना होगा तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। खरगे ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं को धमकियां दी जा रही हैं और पश्चिम बंगाल तथा बिहार में कई युवाओं को जबरन हिरासत में लिया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी सरकार की कथित धमकियों से आज का युवा डरने वाला नहीं है। उन्होंने दावा किया कि विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने वाले युवाओं को धमकियां मिल रही हैं और उनके सोशल मीडिया खातों तक की जांच-पड़ताल की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पहले युवाओं पर लाठी-डंडों और पैलेट गन से हमला किया गया और अब विरोध-प्रदर्शन समाप्त होने के बाद उनके सोशल मीडिया खातों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह एक डरे हुए ''तानाशाह की निशानी'' है।

खरगे ने कहा कि देश के युवा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र और पेपर लीक रोकने के लिए गठित डॉ. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों का 766 दिन बाद भी क्या हुआ।

भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ग्लास्गो/भाषा। एशियाई चैम्पियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रमंडल खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में महिलाओं के 53 किलो वर्ग में रिकार्ड की झड़ी के बीच सोमवार को रजत पदक जीता । छत्तीसगढ के भोंडिया गांव की ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलो और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो समेत कुल 199 किलो वजन उठाया । नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला ने राष्ट्रमंडल और राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड तोड़कर 206 किलो वजन उठाते हुए स्वर्ण पदक जीता । उन्होंने स्नैच में 93 किलो और क्लीन एंड जर्क में 113 किलो वजन उठाया। कनाडा की रेबेका ग्राउल ने 178 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता।

आंकड़े हालांकि पूरी कहानी नहीं बताते । यहां दो युवा भारोत्तोलकों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था।

लगभग हर सफल कोशिश के बाद अधिकारियों को नया खेल रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए तेजी दिखानी पड़ी, क्योंकि ज्ञानेश्वरी और ओनोमे के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी और इस मुकाबले ने खचाखच भरे स्टेडियम में दर्शकों को अपनी सीटों से उठने पर मजबूर कर दिया। स्नैच में ज्ञानेश्वरी के तीनों लिफ्ट साफ सुथरे थे । क्लीन एंड जर्क में शानदार मुकाबला रहा। भारतीय खिलाड़ी ने 107 किलो वजन उठाकर खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया लेकिन ओनोमे ने तुरंत ही 110 किलो वजन उठाकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया । ज्ञानेश्वरी भी हार मानने को तैयार नहीं थी जिन्होंने 111 किलो वजन उठाकर फिर रिकॉर्ड अपने नाम किया।

लोकसभा में आज शुरू हो सकती है लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

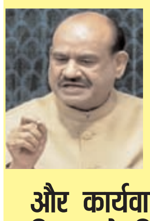

हम समय देने के लिए तैयार हैं तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, आज सदन में इस विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी और कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

नई दिल्ली/भाषा। नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर लोकसभा में जारी गतिरोध दूर करने पर सहमति बन गई है और मंगलवार से सदन में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हो सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा, ''लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सभी प्रमुख राजनीतिक दल मंगलवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2026 पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं।'' प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। बिरला ने सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान सभी दलों से इस विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ''यह हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। यह विधेयक प्रश्नपत्र लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है।'' उन्होंने सत्तापक्ष और विपक्ष को तीन घंटे का समय देते हुए कहा कि ''शाम को पांच बजे तक सरकार और सभी दल मिलकर सहमति बनाएं, ताकि पांच बजे इस विधेयक पर चर्चा शुरू हो सके।'' बिरला ने कहा कि वह इस विधेयक पर चर्चा के लिए छह घंटे का समय देने के लिए तैयार हैं तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, आज सदन में इस विधेयक पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी और कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

स्वागत

राष्ट्रमंडल खेल के कांस्य पदक विजेता पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार का राष्ट्रमंडल खेलों से लौटने के बाद सोमवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचने पर जोरदार स्वागत किया गया।

मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी का आदेश रद्द किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मदुरै/भाषा। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सी. जोसेफ विजय नीत तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार के उस आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया, जिसमें पिछले साल करूर में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया था। न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर. शक्तिवेल की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी विभागों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे कई लोगों की ज़रूरतों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।

पीठ ने कहा कि जब प्रतीक्षा सूची मौजूद हो, तो उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करके करूर घटना के पीड़ितों के परिजनों के लिए ऐसी राहत देना उचित नहीं है। अदालत ने कहा, ''हमारा मानना है कि ये नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत देश के नागरिक को मिली गारंटी का सीधा उल्लंघन हैं।'' पीठ ने कहा कि सरकार की शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। इस बीच, आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, अदालत ने पटाखा निर्माण इकाइयों में हादसों और सड़क दुर्घटनाओं में जान जाने की घटनाओं का भी ज़िक्र किया।

ऐसे मामलों में, पीड़ितों के परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाती है, न कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है। पीठ ने यह भी कहा कि भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के आदेश से इसी तर्ज पर नौकरी की मांग करने वालों की बाढ़ आ जाएगी। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के 31 परिजनों को 10 जुलाई 2026 को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। टीवीके की एक रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे।

नेशनल हेराल्ड मामला

सोनिया और राहुल को ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सोमवार को संबंधित पक्षों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने कहा कि अदालत इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर को करेगी। न्यायमूर्ति जैन ने कहा, हम आज (सोमवार को) इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। पहले से निर्धारित दो अन्य मामलों पर भी आज सुनवाई होनी है। अदालत की वाद सूची में मामलों की संख्या बहुत अधिक हैं।

प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत का फैसला 'पूरी तरह गलत' है और उच्च न्यायालय द्वारा दो महीने पहले समय दिए जाने के बावजूद प्रतिवादियों ने अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी, यह केवल कानून से जुड़ा सवाल है। जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने पहले समय दिया गया था। मैं जवाब दाखिल करने का विरोध नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से कानून का सवाल है।

अदालत ने आदेश दिया, दलीलों के लिए मामले को 10 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए। अगर जवाब दाखिल नहीं किया गया है, तो उसे तीन हफ्तों के भीतर दाखिल किया जाए। उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर 2025 को मुख्य याचिका के साथ-साथ निचली अदालत के 16 दिसंबर के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली ईडी की अर्जी पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों को नोटिस जारी किये थे। स्त्र

निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन स्वीकार्य नहीं है' क्योंकि यह किसी प्राथमिकी पर आधारित नहीं है। उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर गांधी परिवार के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया था। ईडी ने इन सबके अलावा कांग्रेस के दिवंगत नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस पर साजिश रचने एवं धनशोधन का आरोप लगाया है।

महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध का तरीका आज भी प्रासंगिक : सोनम वांगचुक

नई दिल्ली/भाषा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को कहा कि हाल ही में समाप्त हुए छात्रों के आंदोलन की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध का तरीका आज भी प्रासंगिक है। वांगचुक ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्रीय मंत्रियों का उनका अनशन तोड़ने में मदद करना केंद्र सरकार के उनकी (वांगचुक की) मांगों को स्वीकार करने का संकेत था, न कि किसी तरह का राजनीतिक समर्थन। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद वांगचुक ने पीटीआई-भाषा' से कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में, 26 दिन का अनशन समाप्त करने को लेकर उनकी आलोचना लद्दाख की परंपराओं को ठीक से नहीं समझने के कारण की गई।

वांगचुक ने कहा, ''मैं बापू (महात्मा गांधी) को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता था। उनका (अहिंसा का) मार्ग आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना 100 वर्ष पहले था। आज यह प्रयोग सफल साबित हुआ है।'' विवाद पर सफाई देते हुए वांगचुक ने कहा कि लद्दाख में जब कोई सरकारी प्रतिनिधि या वरिष्ठ नेता किसी प्रदर्शनकारी का अनशन तुड़वाता है, तो इसे इस बात का प्रतीक माना जाता है कि सरकार ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली हैं।

भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/चंडीगढ़/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने के बाद कहा कि उन्होंने राज्य के विकास एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

ढिल्लों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 35 मिनट की आमने-सामने की बैठक में उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने फोन पर 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''हमने राज्य में कानून-व्यवस्था, मादक पदार्थ की समस्या और आपराधिक गिरोह जैसे सभी मुद्दों पर चर्चा की।'' उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि उन्हें जब भी बुलाया जाएगा, वह पंजाब जाएंगे।'' ढिल्लों ने जून में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभाला था।

उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका मिला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने लिखा, इस मौके पर हमने पंजाब के समग्र विकास, राज्य के लोगों के कल्याण, पंजाब की रीढ़ समझे जाने वाले किसानों और मजदूरों की भलाई, उद्योगों के विस्तार, पंजाब को फिर से एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए नया निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और राज्य के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने पर विस्तार से सार्थक चर्चा की।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का दूरदर्शी नेतृत्व और पंजाब के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता वाकई प्रेरणादायक है तथा इससे राज्य की तरक्की को एक नई दिशा मिलेगी।

ढिल्लों ने कहा कि भाजपा पंजाब के विकास और वहां के लोगों की सेवा के लिए पूरी लगन एवं ईमानदारी से काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मोदी ने 17 जुलाई को जालंधर दौरे के दौरान 5,470 करोड़ रुपये की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया था, जिनमें 75 नए सिरे से विकसित किए गए रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने तब कानून व्यवस्था, कर्ज एवं भ्रष्टाचार को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा था।

पंजाब में 'आम आदमी क्लिनिक' के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

होशियारपुर/भाषा। पंजाब के 'आम आदमी क्लिनिकों' में कार्यरत डॉक्टर, फार्मासिस्ट और क्लिनिकल सहायकों ने पक्की नौकरी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इसके तहत कर्मचारियों ने राज्य भर में सेवाएं बंद रखीं और विरोध-प्रदर्शन किया।

'आम आदमी क्लिनिक संयुक्त मोर्चा, पंजाब' की अगुवाई में राज्य में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राज्य में 1,000 से अधिक 'आम आदमी क्लिनिक' स्थापित किए हैं, जहां मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य संबंधी जांच की सुविधा दी जाती है।

होशियारपुर में चिकित्सा अधिकारी डॉ. गुरशान और क्लिनिकल सहायक गुरप्रीत कौर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ कई दौर की बैठकें करने और बार-बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद उनकी मांगों को हल करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने सभी 23 जिलों के सिविल सर्जन, स्वास्थ्य सेवा निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह को कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अब तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें अनुबंध व्यवस्था के तहत काम पर रखा गया है, जिससे उनके साथ दैनिक वेतनभोगियों जैसा व्यवहार हो रहा है। उन्हें केवल उन्हीं दिनों का वेतन मिलता है जिन दिनों में वे काम करते हैं, जबकि रविवार या राष्ट्रीय छुट्टियों का कोई भुगतान नहीं किया जाता। इसके अलावा, उन्हें कोई आकस्मिक या चिकित्सीय अवकाश पाने का अधिकार नहीं है।

गुजरात ने पोत निर्माण नीति जारी की, 27 हजार करोड़ रुपये के निवेश पर नजर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। गुजरात सरकार ने सोमवार को अपनी पोत निर्माण नीति जारी की। इस नीति का उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचे के विकास और कौशल विकास के जरिये राज्य को भारत का प्रमुख समुद्री विनिर्माण केंद्र बनाना है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकार की जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 'गुजरात पोत निर्माण एवं मरम्मत नीति- 2026' जारी की। इस नीति का उद्देश्य दो एकीकृत विशाल जहाज निर्माण पार्क बनाना, राज्य की जहाज निर्माण क्षमता को 50 लाख डेडवेट टनेज (डीडब्ल्यूटी) से ज़्यादा करना और 27,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना है। डीडब्ल्यूटी वह अधिकतम वजन है जिसे कोई जहाज सुरक्षित रूप से ले जा सकता है।

इस नीति का उद्देश्य पांच लाख से अधिक लोगों का कौशल विकास करना और क्षमता-निर्माण की प्रशिक्षण देना भी है। नीति जारी करने के अवसर पटेल ने कहा, यह नीति गुजरात में दुनिया भर में मुकाबला करने लायक पोत निर्माण की पारिस्थितिकी तैयार करेगी और 'विकसित गुजरात 2047' और आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को पूरा करने में राज्य की भूमिका को मजबूत करेगी।

राज्य सरकार के मुताबिक, यह नीति केंद्र की 'पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना 2025' और 'समुद्री दृष्टिकोण-2047' के अनुरूप है। बयान के मुताबिक, इस नीति का उद्देश्य समुद्री उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान एवं विकास, स्टार्टअप, सहायक उद्योगों और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर भविष्य के लिए तैयार पोत निर्माण पारिस्थितिकी विकसित करना है। इस नीति के तहत, आधुनिक जहाज गोदी अवसंरचना वाले दो एकीकृत विशाल पोत निर्माण पार्क विकसित किए जाएंगे। इनके साथ ही समुद्री उपकरण विनिर्माण संकुल, परीक्षण सुविधाएं, लॉजिस्टिक समर्थन, अनुसंधान एवं विकास केंद्र और कौशल विकास संस्थान भी बनाए जाएंगे। बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पोरबंदर जिले के कुछाडी में एक विशाल पूर्ण रूप से नये सिरे से पोत निर्माण संकुल की मंजूरी दी है। गुजरात समुद्री बोर्ड इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रहा है, जिससे इसके लागू होने का रास्ता साफ होगा। इस संकुल में दो से तीन विश्वस्तरीय जहाज गोदी और उनसे जुड़े उद्योगों का नेटवर्क होगा, और उम्मीद है कि इस परियोजना से करीब 23,700 करोड़ रुपये का निजी निवेश आएगा।

कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर भारत का बंटवारा कराया, भाजपा ने समान नागरिक संहिता दी : यादव

खंडवा/भाषा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर धार्मिक आधार पर देश का विभाजन कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने सभी नागरिकों पर समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाया है। विधानसभा ने 21 जुलाई को कांग्रेस के भारी हंगामे के बीच मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026' को ध्वनिमत से मंजूरी दी थी।

यादव ने खंडवा में 'बलराम कृषि महोत्सव' को संबोधित करते हुए कहा, ''देश के बंटवारे का पाप अगर किसी के सिर पर है, तो कांग्रेस के सिर पर है।'' मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारत की आजादी से पहले खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू-मुस्लिम विभाजन की राजनीति की जिसका परिणाम देश के बंटवारे के रूप में सामने आया।

यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करके 'एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान' की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। उन्होंने दावा किया कि समान नागरिक संहिता पर राज्य के नागरिकों के सुझाव लिए जाने के दौरान 76 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं ने संहिता का समर्थन किया। कार्यक्रम के दौरान यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। उन्होंने स्थानीय जन प्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग स्वीकार करते हुए खंडवा में पुलिस बटालियन स्थापित करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने एक अन्य स्थानीय मांग स्वीकार करते हुए कहा कि खंडवा एवं मूंदी के बीच सड़क निर्माण के लिए 15 सितंबर से पहले निविदा जारी कर दी जाएगी।

मणिपुर में जारी अशांति से अंतर-समुदायिक संबंध, शिक्षा और अर्थव्यवस्था प्रभावित : खेमचन्द सिंह

इंफाल/भाषा। मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने कहा कि राज्य में लंबे समय से जारी अशांति का अंतर-समुदायिक संबंधों, शिक्षा व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सिंह ने यह बात इंफाल पूर्व जिले के अंद्रो विस क्षेत्र में अंद्रो स्थित नव-निर्मित इमा (मातृ) बाजार तथा खुंगदोंगबाम मापा और वांगखेम सिफाई लीकाई में थौबल नदी पर बने दो पुलों के उद्घाटन के अवसर पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा शांति ही विकास की आधारशिला है और राज्य में जारी अशांति ने सामाजिक सौहार्द को बाधित किया है, युवा पीढ़ी की शिक्षा को प्रभावित किया है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के सभी समुदायों से शांति बहाल करने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा वह तीन मई, 2023 से पहले वाले मणिपुर का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, उस दौरान प्रदेश के सभी 36 समुदाय आपसी सौहार्द के साथ मिल-जुलकर रहते थे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अंद्रो विस क्षेत्र में गांवों को जोड़ने वाली छोटी सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए राज्य सरकार 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करेगी।

नीट परीक्षा में कम अंकों आने से हताश 19 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या

अहिल्यानगर/भाषा। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में 19 वर्षीय एक छात्रा ने कथित तौर पर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। छात्रा के घर से मिले एक सुसाइड नोट से पता चलता है कि 21 जून को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) में कम अंक आने से हताश होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कर्जत तहसील के जलालपुर गांव की रहने वाली अंकिता सांगले ने 25 जुलाई को अपने घर में कथित तौर पर फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उसने हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी और 21 जून को नीट- यूजी की पुन:परीक्षा दी थी। पुलिस अधिकारी के अनुसार, छात्रा के घर से एक पत्र बरामद हुआ है, जिसमें उसने लिखा है कि नीट परीक्षा में कम अंक मिलने के कारण वह अवसाद में थी और इसी वजह से यह आत्मघाती कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि कर्जत पुलिस थाने में इस संबंध में दुर्घटना से हुई मौत का मामला (एडीआर) दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। तीन मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा का पर्चा लीक होने के कारण 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई थी, जिसके नतीजे 16 जुलाई को घोषित किए गए।

अंकित शर्मा हत्याकांड : अदालत ने ताहिर हुसैन, चार अन्य की सजा पर फैसला 31 जुलाई तक सुरक्षित रखा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुई आसूचना ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दी जाने वाली सजा पर अपना फैसला 31 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। पांच दोषियों को दी जाने वाली सजा की अवधि पर दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने अपना फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस ने अदालत से सभी पांचों दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने का अनुरोध किया और कहा कि शर्मा पर लगातार हमला करते हुए वे जानवरों जैसी हरकतों पर उतर आए थे। विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने अदालत में कहा कि दोषियों ने शर्मा का अपहरण किया, बेरहमी से मारपीट की और उनकी हत्या कर दी।

उन्होंने कहा कि शर्मा की मौत के बाद भी वे उन पर वार करते रहे। उन्होंने कहा, ''अंकित शर्मा का अपहरण किया गया और बेरहमी से पीटकर उनकी हत्या कर दी गई। उनके शरीर पर कुल 51 घाव पाए गए, जिनमें से 18 घाव धारदार हथियारों से किए गए थे। इस्तेमाल किए गए हथियारों से इस अपराध के पीछे की मंशा और अपराधियों की क्रूरता का पता चलता है। वे जानवरों जैसी हरकत पर उतर आए थे। शर्मा की मौत के बाद भी वे उन पर हमला करते रहे।''

पांडे ने कहा कि अपराध जघन्य और क्रूर था तथा दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

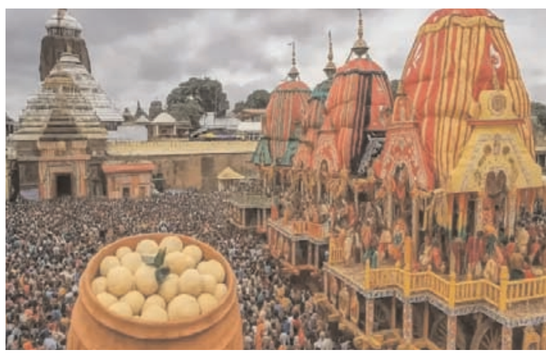

उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री गोपी की याचिका पर शीर्ष अदालत का नोटिस

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय सोमवार को केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने निर्वाचन से जुड़े केरल उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी है।

उच्च न्यायालय ने त्रिशूर सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने त्रिशूर के रहने वाले एवं 'ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन' के नेता बिनॉय ए.एस. को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने गोपी के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

केरल से भाजपा के एकमात्र सांसद गोपी ने उच्च न्यायालय के एक अप्रैल के फ़ैसले को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने कहा था कि बिनॉय की चुनाव याचिका विचार किये जाने योग्य है तथा पर्यटन और पेट्रोलियम राज्य मंत्री को मुकदमे का सामना करने के लिए कहा था। त्रिशूर के सांसद ने चुनाव याचिका को यह कहते हुए चुनौती दी कि यह विचार किये जाने योग्य नहीं है।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने गोपी की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों पर सुनवाई की जरूरत थी।

बिनॉय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि गोपी, उनके चुनाव एजेंट और उनके सहयोगियों ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट तरीके अपनाए।

भगवान जगन्नाथ की पुरी मंदिर में वापसी पर ओडिशा में मनाया गया 'रसगुल्ला दिवस'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। वार्षिक रथ यात्रा के समापन पर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के पुरी स्थित 12वीं सदी के मंदिर में लौटने के उपलक्ष्य में सोमवार को ओडिशा में 'रसगुल्ला दिवस' मनाया गया। 'नीलाद्रि बीजे' के अवसर पर 'रसगुल्ला दिवस' मनाया जाता है।

नीलाद्रि बीजे वह अनुष्ठान है, जिसके तहत तीनों देवी-देवताओं की मंदिर में वापसी होती है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ को विधिवत रसगुल्ले का भोग लगाया जाता है। मंदिर की परंपरा में इस रसगुल्ले को 'खीरा मोहन' कहा जाता है। वर्ष में केवल नीलाद्रि बीजे के दिन ही भगवान जगन्नाथ को रसगुल्ले का भोग लगाया जाता है। हालांकि, मंदिर में यह परंपरा सदियों पुरानी है, लेकिन राज्य में 'रसगुल्ला दिवस' 2015 से मनाया जा रहा है। ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''पावन नीलाद्रि बीजे और रसगुल्ला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महाप्रभु की असीम कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए।'' मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस दिन को उड़िया अस्मिता, संस्कृति और भक्ति की अनूठी अभिव्यक्ति बताया।

उन्होंने कहा, नीलाद्रि बीजे और रसगुल्ला दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीजगन्नाथ का नीलाद्रि बीजे केवल आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक नहीं, बल्कि उड़िया अस्मिता, संस्कृति और भक्ति की अद्वितीय अभिव्यक्ति भी है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कहा कि परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ रसगुल्ला भेंट कर महालक्ष्मी को मनाते हैं। रथ यात्रा में अपने साथ न ले जाने के कारण माता लक्ष्मी भगवान से नाराज रहती हैं। पुरी मंदिर में, रसगुल्ले की उत्पत्ति से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शोधकर्ता असित मोहंती ने कहा कि प्रारंभिक समय में मंदिर में इस मिष्ठान को खीरा मोहन' कहा जाता था और यही आज के समय का रसगुल्ला है।

नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान हिंसा के मामले में दो और लोग गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। कोलकाता पुलिस ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक के विरोध में निकाले गए मार्च के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में सोमवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या अब 16 हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि कोलकाता के गार्डन रीच और पार्क सर्कस इलाकों से दो आरोपियों को पकड़ा गया। अधिकारी ने कहा कि अपराध के घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए गिरफ्तार पांच लोगों को जांच के तहत सोमवार को फिर से एस्प्लेनेड के डोरिना क्रॉसिंग ले जाया गया।

जांच अधिकारियों ने जब अपराध के घटनाक्रम को फिर से दोहराया तो आरोपियों को पुलिस की सुरक्षा में नंगे पैर उस जगह तक ले जाते हुए देखा गया। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अपराध के घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और उसकी पुष्टि करने तथा हर आरोपी की अलग-अलग भूमिका का पता लगाने के लिए अपराध के घटनाक्रम को फिर से दोहराया गया। सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है, जिसमें वीडियो फुटेज, डिजिटल सामग्री और गवाहों के बयान शामिल हैं। अगर और लोगों की भूमिका का पता चलता है तो और गिरफ्तारियां की जाएंगी।

पुलिस ने हाल में गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान पार्क सर्कस के कड़ेया इलाके के रहने वाले 35 साल के वकार आजम और गार्डन रीच के पास नाडियाल थाना क्षेत्र के 32 साल के जावेद अख्तर के तौर पर की है। जांच अधिकारियों का आरोप है कि शुक्रवार को हुए प्रदर्शन मार्च के दौरान हिंसा और तोड़-फोड़ में दोनों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। अधिकारी ने बताया कि घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए जांच के तहत मौके पर ले जाए गए पांच आरोपियों में मोहम्मद अफरोज भी शामिल था।

नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन

कोलकाता/भाषा। कोलकाता पुलिस ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक के विरोध में निकाले गए मार्च के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में सोमवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया, जिससे इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या अब 16 हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि कोलकाता के गार्डन रीच और पार्क सर्कस इलाकों से दो आरोपियों को पकड़ा गया। अपराध के घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए गिरफ्तार पांच लोगों को जांच के तहत सोमवार को फिर से एस्प्लेनेड के डोरिना क्रॉसिंग ले जाया गया।

मैत्रेयी कॉलेज ने 'सुगम' लॉन्च किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रेयी कॉलेज ने 'प्रोजेक्ट सुगम' लॉन्च किया है। यह भारत का पहला ऐसा इनडोर नेविगेशन सिस्टम है, जिसे विद्यार्थियों ने बनाया है और सभी के लिए सुलभ है। इस पहल के ज़रिए, विद्यार्थियों ने सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जिससे देखने, सुनने और चलने-फिरने में अक्षम लोग बिना किसी सहारे के, सम्मानपूर्वक आ-जा सकेंगे। इस कार्यक्रम में सुगम के संस्थापक डॉ. मैथ्यू वर्गीज़ भी शामिल हुए। सुगम के साथ, दिव्यांगजन भी कैंपस की ज़िंदगी में पूरी तरह से हिस्सा ले सकेंगे।

इस कार्यक्रम में मैत्रेयी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रो. हरितिमा चोपड़ा, प्रोजेक्ट लीड प्रो. स्मृति सिंह, नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत और दिल्ली विवि के रजिस्ट्रार भी मौजूद थे। उन्होंने इस पहल और इसमें स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल की तारीफ़ की। प्रो. स्मृति सिंह ने पूरी सुगम टीम का आभार जताया।

संघर्षशील अभिनेता के मरणोपरांत अंगदान से चार लोगों को मिली नई जिंदगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

इंदौर/भाषा। अभिनय की दुनिया में पहचान बनाने का सपना देखने वाले इंदौर के गौरव दवे (25) भले ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके, लेकिन उनके मरणोपरांत अंगदान ने सोमवार को चार लोगों को नई जिंदगी की राह दे दी।

अधिकारियों ने बताया कि दवे का हृदय हवाई मार्ग से अहमदाबाद भेजकर वहां के एक रोगी में प्रतिरोपित किया गया, जबकि उनके यकृत और दो गुर्दे इंदौर के मरीजों में लगाये गये। उन्होंने बताया कि अभिनय के साथ ही कास्टिंग' (अभिनेता चयन) के क्षेत्र में भी काम कर रहे दवे 'ब्रेन हेमरेज' के बाद 13 जुलाई से एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती थे।

अधिकारियों के मुताबिक चिकित्सकों ने जांच के बाद रविवार (26 जुलाई) को उन्हें दिमागी रूप से मृत (ब्रेन डेड) घोषित कर दिया जिसके बाद उनके परिजन अंगदान के लिए सहमत हो गए। अधिकारियों ने बताया कि दवे का हृदय एक नियमित उड़ान से अहमदाबाद भेजा गया जहां उसे अस्पताल में भर्ती 28 वर्षीय एक पुरुष के शरीर में प्रतिरोपित किया गया। उन्होंने बताया कि दवे का यकृत इंदौर के 42 वर्षीय पुरुष में लगाया गया, जबकि दो गुर्दे शहर की 22 वर्षीय महिला और 52 वर्षीय महिला को प्रतिरोपित किए गए। दवे के दोस्त नरेंद्र राठौर ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि दवे मनोरंजन उद्योग में अभिनेता के रूप में पहचान बनाने का सपना देखते थे और एक तेलुगु फिल्म एवं एक वेब सीरीज में काम भी कर चुके थे। राठौर के अनुसार उपचार के दौरान जब दवे की हालत में कुछ सुधार हुआ था, तब उन्होंने अपने एक अन्य मित्र से कहा था कि मरने के बाद उनके अंग दान कर दिए जाएं ताकि उनके अंगों से जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सके।

राठौर ने बताया कि बाद में दवे की हालत फिर बिगड़ गई और चिकित्सकों की कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने कहा, ''इकलौते बेटे को खोने का दुख दवे के परिवार के लिए असहनीय है, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ने उन्हें उनके मरणोपरांत अंगदान का कठिन फैसला लेने का साहस दिया।'' अधिकारियों ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से अंगदाताओं को दिए जाने वाले 'गार्ड ऑफ ऑनर' के तहत दवे को अंतिम विदाई के समय राजकीय सम्मान भी दिया गया।

पूर्ववर्ती द्रमुक सरकार के कथित भ्रष्टाचार पर ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। पूर्ववर्ती द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार पर तैयार 'ऑडिट रिपोर्ट' आगामी बजट सत्र में सदन के पटल पर रखी जाएगी।

तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने यह जानकारी देते हुए विपक्षी दल पर कथित पार्टी फंड संग्रह में अनियमितताओं के मामले में अनभिज्ञता जताने का आरोप लगाया। विल्सन ने बिना नाम लिए द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता पी. के. शेखर बाबू की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में कथित अनियमितताओं का विस्तृत ब्योरा होगा और इससे उस पूर्व मंत्री की भूमिका भी उजागर होगी, जो वर्तमान में हार्बर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''जो पूर्व मंत्री इस समय इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे द्रमुक के कार्यकाल के दौरान एकत्र किए गए पार्टी फंड के बारे में अनभिज्ञ होने का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि 'पार्टी फंड' क्या होता है?' हार्बर विधानसभा क्षेत्र में अपने पहले कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूं, इसलिए इस पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। पूर्ववर्ती द्रमुक सरकार के कार्यकाल में पार्टी फंड जुटाने के नाम पर किए गए कथित भ्रष्टाचार की ऑडिट रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। इसे आगामी बजट सत्र में सदन के पटल पर पेश किया जाएगा।

हार्बर विधानसभा क्षेत्र में रविवार देर शाम आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने द्रमुक के पूर्व मंत्री पी. के. शेखर बाबू का नाम लिए बिना कहा, इसमें कथित भ्रष्टाचार की पूरी सूची होगी। इसके बाद इस पूर्व मंत्री की भूमिका भी उजागर हो जाएगी। मंत्री ने नीट का उल्लेख करते हुए दावा किया कि जिस तरह 2026 में तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने विधानसभा चुनाव जीता, उसी तरह 2029 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में भी राजनीतिक परिवर्तन होगा, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर की इस प्रवेश परीक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा। कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र वितरित करने के लिए आयोजित समारोह में उन्होंने कहा, नीट परीक्षा का स्थायी समाधान निकलेगा। हमारी पार्टी, तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके), का नेतृत्व इस परीक्षा को पूरी तरह समाप्त कराने की दिशा में सक्रियता से काम कर रहा है। यह बदलाव पूरे देश में दिखाई देगा।

बाद में जब संवाददाताओं ने सदन में पेश की जाने वाली लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के बारे में विस्तार से पूछना चाहा, तो विल्सन ने केवल इतना कहा, इंतजार कीजिए और देखिए। उन्होंने संकेत दिया कि इस संबंध में जानकारी मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय देंगे। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का पहला बजट पांच अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया जाएगा। उसी दिन विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें सत्र की अवधि तय की जाएगी।

मेकेदातु बांध के लिए एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी, सीएम विजय इसकी इजाजत नहीं देंगे : राजस्व मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयंबटूर। तमिलनाडु के राजस्व मंत्री ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक को प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कावेरी के पानी पर तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के पक्के स्टैंड को दोहराया। मेकेदातु प्रोजेक्ट पर तमिलनाडु के विरोध को दोहराते हुए के.ए. सेंगोत्तैयान ने ऐलान किया कि कर्नाटक को इस प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मेकेदातु डैम के लिए एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय इसकी इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने राज्य सरकार के नीट के विरोध, कोयंबटूर और मदुरै में प्रस्तावित मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, एआईएडीएमके विधायक डिसक्वालिफिकेशन मुद्दे और आने वाले राज्य बजट पर भी बात की।

कोयंबटूर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय अच्छा शासन दे रहे हैं और पूरे तमिलनाडु में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज करने के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने और दोनों शहरों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल चलाना चाहते हैं। सेंगोट्टैयन ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी और सपोर्ट मांगने के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे तमिलनाडु में सुनियोजित विकास के लिए पक्के इरादे वाले व्यक्ति हैं।

एआईएडीएमके के चार विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ने कहा कि एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी की मौजूदगी में स्पीकर को सीधी जांच की मांग करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। उन्होंने भरोसा जताया कि स्पीकर मामले की जांच करने के बाद सही फैसला लेंगे।

नीट को लेकर उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को प्राथमिकता में रखा गया है। राज्य सरकार की बात को दोहराते हुए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विजय तमिलनाडु के छात्रों को नीट से छूट दिलाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को साफ तौर पर बताया था कि परीक्षा से राज्य के छात्रों पर बुरा असर पड़ रहा है और केंद्र सरकार से पॉलिसी पर फिर से विचार की अपील की गई है।

मंत्री के मुताबिक, सरकार छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सभी संवैधानिक और कानूनी विकल्प अपनाती रहेगी। तमिलनाडु के आगामी बजट को लेकर मंत्री ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया और कहा कि जब तक इसे विधानसभा में पेश नहीं किया जाता, तब तक यह गोपनीय रहेगा। उन्होंने कहा कि बजट पेश होने के बाद इसके प्रावधान स्पष्ट हो जाएंगे।

बैंक ऑफ बड़ौदा में कर्मचारी के ई-मेल से डेटा तक अनधिकृत पहुंच का मामला आया सामने

चेन्नई/मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने सोमवार को कहा कि उसके एक कर्मचारी का ई-मेल अकाउंट से छेड़छाड़ होने के कारण कुछ डेटा तक अनधिकृत पहुंच का मामला सामने आया है। हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया कि उसकी मुख्य बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनमें कोई सेंध नहीं लगी है। बैंक ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, यह घटना एक कर्मचारी के ई-मेल अकाउंट के साथ छेड़छाड़ से जुड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ डेटा तक अनधिकृत पहुंच हुई। बीओबी ने कहा कि इस घटना की पहचान समय पर कर ली गई और हालात को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल कदम उठाए गए। हालांकि, बैंक ने यह नहीं बताया कि ई-मेल अकाउंट से छेड़छाड़ की यह घटना कब हुई या संबंधित कर्मचारी किस पद पर तैनात था। बैंक का यह बयान मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही उन चर्चाओं के बीच आया है, जिनमें दावा किया गया था कि एक टीबी से अधिक डेटा, जिसमें ग्राहकों के आधार से जुड़े विवरण भी शामिल हैं, को अनधिकृत रूप से पहुंच बनाकर डार्क वेब पर साझा किया गया है। बीओबी ने कहा कि उसके पास मजबूत सूचना सुरक्षा व्यवस्था मौजूद हैं और मामले की व्यापक फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही, वह संबंधित प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

केवीबी ने तिमाही वित्तीय परिणामों को घोषणा की

चेन्नई। करूर वैश्य बैंक ने 30 जून को समाप्त वित्तीय वर्ष 2027 के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा की है । बैंक द्वारा जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार बैंक का कुल व्यवसाय रु 2,27,267 करोड़ हो गया है जिसमें, प्रति वर्ष 15.94 प्रतिशत और तिमाही-दर-तिमाही 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार बैंक का शुद्ध लाभ 44.92 प्रतिशत से बढ़कर रु 756 करोड़ हो गया जो अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ है। इसी प्रकार बैंक द्वारा अर्जित शुद्ध ब्याज आय 31.76 प्रतिशत से बढ़कर रु 21423 करोड़ हो गया है जबकि एनआइएम 4.34 प्रतिशत पर स्थिर है। सीएएसए अनुपात 27.55 प्रतिशत दर्ज किया गया। जीएनपीए 0.74 प्रतिशत और एनएनपीए 0.19 प्रतिशत है जो बैंक की मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता को दर्शाता है। इसी प्रकार पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 18.61 प्रतिशत है । बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बी. रमेश बाबू ने इस अवसर पर कहा कि विकास, लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंक ने तिमाही में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है बैंक भविष्य में और अच्छे एवं शानदार नतीजे प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक का पहली तिमाही का शुद्ध लाभ 35 प्रतिशत बढ़कर 412 करोड़ रुपये

नई दिल्ली/चेन्नई। निजी क्षेत्र के तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (टीएमबी) का वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 35 प्रतिशत बढ़कर 412 करोड़ रुपये हो गया। बैंक की मुख्य आय में वृद्धि से उसका लाभ बढ़ा है। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में 305 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। टीएमबी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 1,901 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 1,617 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन तिमाही में बैंक की ब्याज आय बढ़कर 1,662 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की जून तिमाही में 1,386 करोड़ रुपये थी। पहली तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 32 प्रतिशत बढ़कर 765 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 580 करोड़ रुपये थी। तिमाही नतीजों के बाद मीडिया से बातचीत में तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) सली सुकुमारन नायर ने कहा कि बैंक प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) से जमा जुटाने के लिए विदेश में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की संभावना तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अवसंरचना और मोबाइल ऐप समेत अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर 280 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके अलावा, बैंक तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में अपनी उपस्थिति का विस्तार करेगा। बैंक की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जून तिमाही के अंत में उसका सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात घटकर कुल अग्रिम का 0.69 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले 1.22 प्रतिशत था। इसी तरह, शुद्ध एनपीए यानी फंसे हुए कर्ज का अनुपात 0.17 प्रतिशत रहा, जो एक साल पहले 0.33 प्रतिशत था।

तमिलनाडु में बिना वैध पंजीकरण संचालित एम-सैंड इकाइयों पर सरकार की सख्ती, जल्द होगी कार्रवाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद खनिज संसाधन क्षेत्र में अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अचानक किए जा रहे निरीक्षणों में खनन और मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड) उत्पादन से जुड़े नियमों में बड़े पैमाने पर उल्लंघन सामने आए हैं।

राज्य के खान एवं खनिज मंत्री प्रभु कई जिलों में बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को खनन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले खदानों को सील करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने अवैध खनन गतिविधियों को रोकने में विफल रहने या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के संदेह में खनिज संसाधन विभाग के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला भी किया है। सरकार की सख्त कार्रवाई के कारण शुरुआत में एम-सैंड की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली क्योंकि उत्पादकों ने काले ग्रेनाइट की खदानों पर सख्ती के चलते उत्पादन प्रभावित होने का हवाला दिया था। हालांकि, खान एवं खनिज मंत्री ने उद्योग संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें स्थिति का अनुचित लाभ उठाने के खिलाफ चेतावनी दी, जिसके बाद प्रस्तावित मूल्य वृद्धि वापस ले ली गई।

इसी दौरान सरकार ने एम-सैंड निर्माण इकाइयों द्वारा किए गए कथित नियम उल्लंघनों की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं। भूविज्ञान एवं खनन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एम-सैंड कठोर काले पत्थरों को क्रश और प्रोसेस करके तैयार किया जाता है और इसे पर्यावरणीय कारणों से सीमित किए जा रहे नदी की प्राकृतिक रेत के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु सरकार लंबे समय से निर्माण कार्यों में प्राकृतिक नदी की रेत के टिकाऊ विकल्प के रूप में एम-सैंड के उपयोग की सिफारिश करती रही है।

अधिकारी ने बताया कि सभी एम-सैंड निर्माण इकाइयों के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इन पंजीकरणों का गुणवत्ता और संचालन संबंधी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आमतौर पर हर तीन से पांच वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होता है।

तमिलनाडु में वर्तमान में 506 पंजीकृत एम-सैंड निर्माण इकाइयां हैं। हालांकि, हाल ही में पंजीकरण रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि इनमें से लगभग 40 प्रतिशत इकाइयों, यानी करीब 200 फैक्ट्रियों ने अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है। अधिकारियों ने यह भी पाया है कि इनमें से कई इकाइयां अनिवार्य नवीनीकरण कराए बिना तीन वर्ष से अधिक समय से उत्पादन जारी रखे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस लापरवाही से निर्माण क्षेत्र में आपूर्ति किए जा रहे एम-सैंड की गुणवत्ता और नियामकीय अनुपालन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। चूंकि ये इकाइयां बिना अद्यतन पंजीकरण के संचालित हो रही हैं, इसलिए सरकार अब इनके खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर विचार कर रही है।

बताया गया कि इस मुद्दे पर हाल ही में मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में भूविज्ञान एवं खनन विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भी चर्चा हुई।

अधिकारियों के अनुसार, वैध पंजीकरण के बिना संचालित एम-सैंड निर्माण इकाइयों के खिलाफ जल्द ही प्रवर्तन कार्रवाई शुरू किए जाने की संभावना है। यह कदम राज्य के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बहाल करने के व्यापक अभियान का हिस्सा होगा।

उदयनिधि स्टालिन ने जेल में विधायक से की मुलाकात, गिरफ्तारी को लेकर उठाये सवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुनेलवेली/भाषा। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को पलायमकोट्टई केंद्रीय कारागार में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के विधायक जी वी मार्कंडेयन से मुलाकात करने के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उदयनिधि ने कहा, सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त करने वालों के साथ-साथ विपक्षी दलों के पदाधिकारियों के खिलाफ अनावश्यक और झूठे मामले दर्ज करना ही इस सरकार का एकमात्र काम लगता है।

द्रमुक नेता ने कहा कि उन्होंने मार्कंडेयन को भरोसा दिलाया है कि द्रमुक नेतृत्व उन्हें सभी जरूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। उदयनिधि स्टालिन ने मार्कंडेयन से करीब 30 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने कहा, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अप्पावु, गीता जीवन और अनिता राधाकृष्णन के साथ मैंने विलाथिकुलम से अपने विधायक और प्रिय भाई मार्कंडेयन से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। मार्कंडेयन को तूतीकोरिन में पुलिस में दर्ज एक शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मार्कंडेयन ने कोविलपट्टी में एक सार्वजनिक सभा के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ मानहानिकारक और धमकी भरी टिप्पणी की थी। द्रमुक विधायक को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित रूप से 'हम आपकी हड्डियां तोड़ देंगे' वाली टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था।

अयोग्यता मामले में पलानीस्वामी और पूर्व विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश होने को कहा गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के प्रमुख एडप्पादी के. पलानीस्वामी और उनकी पार्टी के चार पूर्व विधायकों को 30 जुलाई को तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जे. सी. डी. प्रभाकर के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह सुनवाई दल-बदल विरोधी कानून के तहत चारों पूर्व विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में होगी।

चारों विधायक-मरगथम कुमारवेल (मदुरांतकम विधानसभा क्षेत्र), पी. सत्यबामा (धारापुरम), एस. जयकुमार (पेरुंदुरई) और एसक्की सुबैया (अंबासमुद्रम) चुनाव जीतने के एक महीने से भी कम समय के भीतर अन्नाद्रमुक छोड़कर सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) में शामिल हो गए थे। एक अधिकारी के अनुसार, विधानसभा सचिवालय की ओर से विधानसभा सचिव आर. शांति ने 24 जुलाई को समन जारी किए थे। इसमें अध्यक्ष के आदेश का हवाला देते हुए चारों को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अलग-अलग पेश होकर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है। सदन में अन्नाद्रमुक के नेता पलानीस्वामी ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत मरगथम कुमारवेल, सत्यबामा, जयकुमार और एसक्की सुबैया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इन विधायकों ने पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया और सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) में शामिल हो गए। चारों विधायकों में से प्रत्येक को अपना पक्ष रखने के लिए पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 12.30 बजे के बीच अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। ये चारों उन 25 बागी अन्नाद्रमुक विधायकों में शामिल थे, जिन्होंने पार्टी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए 13 मई को हुए विश्वास मत परीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया था। बाद में, अन्नाद्रमुक के महासचिव पलानीस्वामी ने 21 विधायकों को पार्टी में वापस स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने मतभेद दूर कर उनके नेतृत्व में काम करने पर सहमति जताई थी। हालांकि, उन्होंने इन चार विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जारी रखी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी के आदेश को किया रद्द

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पिछले साल करूर में हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया था। अदालत ने कहा कि भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने संबंधी आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। पीठ ने यह भी कहा कि भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के आदेश से इसी तर्ज पर नौकरी की मांग करने वालों की बाढ़ आ जाएगी। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के 31 परिजनों को 10 जुलाई 2026 को नियुक्ति पत्र सौंपे थे।

शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर स्कूली छात्रा की गर्दन पर चाकू से हमला, आरोपी ने की आत्महत्या

चिदंबरम/भाषा। शादी का प्रस्ताव कई बार ठुकराए जाने पर एक युवक ने 16 वर्षीय स्कूली छात्रा की गर्दन पर कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया। छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 27 वर्षीय आरोपी अयप्पन ने सोमवार को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार को कडलूर जिले के कीझामूंगलाडी गांव स्थित पीड़िता के घर पर हुई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अयप्पन कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा के घर अक्सर बिजली मरम्मत का काम करने आता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान वह उसके प्रति आकर्षित हो गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, उसने कई बार नाबालिग छात्रा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने हर बार उसे ठुकरा दिया। पुलिस के अनुसार, छात्रा की मां कपड़े की एक दुकान पर काम करने के लिए घर से बाहर गई थी। पुलिस ने बताया कि इसका फायदा उठाकर अयप्पन रविवार को उस समय घर में घुस गया, जब किशोरी अकेली थी। पुलिस के मुताबिक, छात्रा ने एक बार फिर उसका शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद उसने चाकू से लड़की की गर्दन पर तेजी से वार किया और मौके से फरार हो गया।

एकीकृत जल प्रबंधन से राजस्थान में जल सुरक्षा और कृषि समृद्धि को मिलेगी नई दिशा : श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में जल संसाधनों के दीर्घकालिक, टिकाऊ एवं अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राजस्थान नदी बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग अथॉरिटी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में जल सुरक्षा, पेयजल आपूर्ति तथा सिंचाई क्षमता के विस्तार हेतु सभी 11 संबंधित विभागों को अंतर-विभागीय समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक का मुख्य एजेंडा प्रदेश के प्रत्येक नदी बेसिन में जल की उपलब्धता, वर्तमान परियोजनाओं एवं उनमें आ रही चुनौतियों की समीक्षा तथा 'विकसित राजस्थान2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों के तालमेल से एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के अनुरूप योजना बनाना और जल क्षेत्रों को प्रदूषण से बचाना रहा।

मुख्य सचिव ने जल संसाधन सहित प्राधिकरण से सम्बंधित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में वर्तमान में उपलब्ध सीमित जल के समुचित एवं अधिकतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों के तालमेल से प्रत्येक बेसिन की समग्र परियोजना तैयार की जाए। परियोजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन, जल वितरण एवं कमान क्षेत्र के सुव्यवस्थित प्रबंधन हेतु कमान क्षेत्र विकास गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रही जल संसाधन परियोजनाओं, नहरी तंत्रों एवं अधूरे पड़े कार्यों को निर्धारित समयावधि में प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि आमजन को उनका त्वरित लाभ मिल सके।

वी. श्रीनिवास ने कृषि में जल की हर बूंद के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु नहरी दक्षता बढ़ाने तथा ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं सोलर आधारित पाइपलाइन योजनाओं को व्यापक स्तर पर अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवार जल उपलब्धता को देखते हुए किसानों को कम पानी में अधिक उपज देने वाली फसलों को अपनाने हेतु जागरूक व प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, नदियों और जलाशयों के सतही जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए पेयजल आपूर्ति के लिए भूजल पर निर्भरता कम करने और डार्क जोन की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 1990 के दशक के मध्य के बाद से सभी 16 नदी बेसिन योजनाओं का समयबद्ध अद्यतनीकरण किया जा रहा है, जिसके तहत आधुनिक तकनीकों, जल दक्षता और नहरी सुधारों के बल पर प्रदेश के सिंचाई कमांड क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बेसिनों के प्रस्तुतीकरण संबंधित हितधारक विभागों को भिजवाकर उनसे त्वरित टिप्पणी एवं सुझाव प्राप्त किए जाएं। बैठक के प्रारंभ में राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता राज पाल सिंह ने प्राधिकरण के गठन एवं कार्यों की जानकारी दी। माही परियोजना के मुख्य अभियंता ने माही बेसिन के विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया, जिसके अंतर्गत बजट घोषणाओं के अनुसार माही बेसिन के अधिशेष जल को जयसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जवाई बांध तथा लूनी बेसिन तक पहुँचाने की योजनाओं की डीपीआर एवं प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य अभियंता, हनुमानगढ़ ने उत्तर संभाग (हनुमानगढ़, गंगानगर) में सीमित सतही जल एवं रावी, व्यास तथा सतलज नदियों से अंतरराज्यीय समझौतों के तहत प्राप्त जल की स्थिति पर प्रकाश डाला। मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर विवेक गोयल ने परियोजना में प्राप्त हो रहे जल तथा निर्माणाधीन 4 जल संग्रहण संरचनाओं की जानकारी दी। मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग कोटा ने चंबल बेसिन की परियोजनाओं तथा राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध एवं कोटा बैराज की स्थिति से अवगत कराया, जिस पर मुख्य सचिव ने राणा प्रताप सागर से बीसलपुर बांध में जल लाने वाली ब्राह्मणी परियोजना के महत्व पर विशेष बल दिया। जोधपुर संभाग की चर्चा के क्रम में अतिरिक्त मुख्य अभियंता, पाली ने बांडी एवं जोजरी नदी के प्रदूषण तथा उसके निवारण हेतु जारी प्रयासों पर प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें डी-स्लजिंग, एसटीपी संचालन एवं मुख्यधारा चैनल निर्माण कार्यों में तेजी लाने की बात कही गई। मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग जोधपुर ने नर्मदा नहर परियोजना की विस्तृत जानकारी दी।

गहलोत का राजस्थान की भाजपा सरकार पर 300 से अधिक भूमि आवंटन रद्द करने का आरोप

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सोमवार को आरोप लगाया कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के समय आवंटित 300 से ज्यादा भूखंडों के आवंटन रद्द कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बदले की भावना में यह कार्रवाई की है। गहलोत ने एक बयान में कहा, हमारी कांग्रेस सरकार के समय विभिन्न विभागों में समाजों, संस्थाओं एवं जनकल्याणकारी प्रयोजनों हेतु किए गए 300 से अधिक भूमि आवंटन भाजपा सरकार ने रद्द कर दिए हैं। इनमें से अधिकांश संस्थाओं द्वारा अमानत राशि जमा कराने के बावजूद आवंटन निरस्त कर दिए गए।

उन्होंने कहा कि ये आवंटन किसी पार्टी के नहीं बल्कि गांव-ढाणी से पढ़ने आने वाले बच्चों के छात्रावास, सामाजिक संस्थाओं एवं जनसुविधाओं के लिए थे। गहलोत ने कहा, इन्हें रद्द करना समाजों का अपमान एवं युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है। इससे समाजों में भयंकर आक्रोश है। परन्तु विडंबना देखिए, इसी सरकार के पास भाजपा के नए प्रदेश मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों के लिए जमीनों की कोई कमी नहीं है। वहां आवंटन की फाइलें दिन-रात दौड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया, क्या राजस्थान की जमीन सिर्फ भाजपा के दफ्तरों के लिए है, पिछड़े समाजों, हमारे बच्चों के लिए नहीं है? क्या इन जेन-जी बच्चों को भाजपा गंभीरता से नहीं लेती है? उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। गहलोत ने कहा,सरकार श्वेत पत्र जारी कर बताए कि किन-किन आवंटनों को, किस आधार पर रद्द किया गया। बदले की भावना से किए गए ये सभी निर्णय तुरंत वापस लिए जाएं और सभी आवंटन पुन: बहाल किए जाएं।

दिया कुमारी ने मारवाड़ में विकास कार्यों का किया शिलान्यास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन दौरे पर रहीं। जहां उन्होंने स्टेट हाईवे 61 स्काई ओवर ब्रिज का व करोड़ो रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय स्थित झाड़रियां हनुमान मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। सिरियारी और सवराड़ गांव की नदियों पर बने पुलों तथा रानी-भिवाड़िया सड़क मार्ग के नवीनीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया।

उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुये कहा कि सरकार ने समयबद्ध रूप से योजना बनाकर कम समय में तेज व आधुनिक तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में सरकार ने गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों को धरातल पर उतारकर जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से सड़क, पुल और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़े कार्य गुणवत्ता के साथ पूरे किए जा रहे हैं तथा सरकार विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। उपमुख्यमंत्री ने लोगों से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन कर देश प्रदेश खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी इसके बाद सोजत नगर पालिका पहुंचीं। उन्होंने वहां शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर लाभार्थियों को पट्टा वितरण किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने नगर पालिका में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली व उनके प्रभार वाले विभागों की योजनाओं, प्रगति व बकाया कामों की जानकारी ली व संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

उन्होंने राजयोजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी उधम योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओं बेटी पढाओ योजना, में पाली जिले की स्थिति व प्रगति लाने के निर्देश दिये व विभिन्न प्रकरणों की प्रगति की जानकारी ली।

इसी प्रकार अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। इस अवसर पर सोजत विधायक शोभा चौहान, मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी सहित सभी संबंधित विभागों के जिला व ब्लॉक लेवल अधिकारी जनप्रतिनिधिगण आदि मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने औद्योगिक पार्कों के प्रस्तावों की समीक्षा कर डीपीआईआईटी को प्रेषित करने को दी मंजूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) द्वारा विकसित किए जा रहे औद्योगिक पार्कों के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। समिति ने इन प्रस्तावों को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (उद्धखख), भारत सरकार को अनुमोदन एवं आगे की कार्यवाही के लिए प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य शिखर अग्रवाल ने भव्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित चार औद्योगिक पार्कों - केबीएनआईआर (घइख्खद) इंडस्ट्रियल पार्क, कोटपूतली-बहरोड़; दौसा-बांदीकुई इंडस्ट्रियल पार्क, भोज्यारा इंडस्ट्रियल पार्क, जयपुर; तथा उदयपुर कलां इंडस्ट्रियल पार्क, किशनगढ़ (अजमेर) के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

उन्होंने बताया कि भव्य केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे डीपीआईआईटी द्वारा 10 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया गया है। योजना का उद्देश्य देशभर में निवेश के लिए तैयार विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करना है। 23 मई 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2031-32 तक संचालित होने वाली इस योजना के तहत लगभग 33 हजार 600 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन पार्कों का चयन दो या अधिक चरणों में किया जाएगा, जिनमें प्रथम चरण में अधिकतम 50 परियोजनाओं को शामिल किए जाने का प्रावधान है। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रस्तावित चारों औद्योगिक पार्कों का कुल क्षेत्रफल लगभग 2 हजार एकड़ है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 8 हजार से 10 हजार करोड़ रुपये तक के निवेश तथा 45 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन की प्रबल संभावना है। प्रस्तुतीकरण में पार्कों के लिए चयनित स्थलों की विशेषताओं, सेक्टर-विशिष्ट विकास, अवसंरचना योजना, कनेक्टिविटी, भूमि उपलब्धता तथा निवेश एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि ये प्रस्ताव राज्य में सेक्टर-विशिष्ट औद्योगिक विकास को गति देने, विनिर्माण पारितंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा मेक इन इंडिया एवं एकीकृत औद्योगिक कॉरिडोर जैसी राष्ट्रीय पहलों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। बैठक में बताया गया कि फेज-1 राउंड-1 के अंतर्गत 1 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें 20 प्रस्तावों का चयन किया जाएगा। वहीं फेज-1 राउंड-2 के लिए 1 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसमें 30 प्रस्तावों का चयन किया जाएगा।

पेपर लीक माफियाओं पर लगेगी लगाम, युवाओं के भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़ : प्रेम चंद बैरवा

जयपुर । राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने पेपर लीक रोकने के उद्देश्य से लाए गए विधेयक का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने इसे परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सरकार का सख्त कदम बताया। उन्होंने दावा किया कि इस कानून से भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। वहीं, उन्होंने भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दूसरी ओर, मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का समर्थन करते हुए नागरिकों से अपने घरों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की। पेपर लीक रोकने वाले विधेयक पर उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों को लेकर हमेशा गंभीर रही है। पूर्व में हुई पेपर लीक की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैबिनेट से विधेयक को मंजूरी दी और अब इसे लोकसभा में पेश किया गया है। इस कानून के लागू होने से पेपर लीक माफियाओं पर प्रभावी लगाम लगेगी और आने वाले समय में विद्यार्थियों एवं युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार का अन्याय या खिलवाड़ नहीं होगा। सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है ताकि युवाओं का विश्वास बना रहे। मीराबाई चानू की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए बैरवा ने कहा कि वह पूरे देशवासियों को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई।

मानसून फिर सक्रिय होने की उम्मीद, 29 से कई इलाकों में भारी बारिश के आसार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान में इस सप्ताह मानसून के फिर तेज होने की संभावना है और आगामी दिनों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को यह जानकारी दी। आईएमडी के जयपुर केंद्र के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र गहरा होकर 'अवदाब' में बदल गया है। इसके आगे बढ़ने के प्रभाव से 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।

विभाग के अनुसार, 29 जुलाई से दो अगस्त तक राज्य के अधिकांश भागों में मानसून एक बार फिर सक्रिय रहेगा और झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार हैं। नए मौसमी तंत्र के सक्रिय होने से बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी 29 जुलाई से दो अगस्त के बीच वर्षा होने का अनुमान है। इस बीच, सोमवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। जालौर और सिरोही जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई। सर्वाधिक 86.5 मिलीमीटर बारिश सिरोही जिले के आबू रोड में दर्ज की गई।

नाबालिग बच्ची की खरीद-फरोख्त के आरोपियों की अवैध संपत्ति ध्वस्त

जयपुर।राजस्थान के अजमेर में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने नाबालिग बच्ची की खरीद-फरोख्त के आरोपियों की अवैध निर्माण ढहाना शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार दरगाह थानाक्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची को 32 हजार रुपये में बेचे जाने के गंभीर मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्तियों और अतिक्रमणों को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया।

सड़क दर्घटना में मुख्य आरक्षी समेत तीन की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में तेज रफ्तार 'बोलेरो' (एक चौपहिया वाहन) की टक्कर से दो मोटरसाइकिलों पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जिन लोगों की जान गयी उनमें एक राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी (आरएसी) का एक मुख्य आरक्षी था। पुलिस के अनुसार, यह हादसा रविवार रात वरदा थाना क्षेत्र के अंतरी के पास हुआ। थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान 13वीं आरएसी बटालियन के मुख्य आरक्षी धूलसिंह चौहान (55), उनके चचेरे भाई महिपाल सिंह (54) और दिनेश रोत (21) के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, धूलसिंह ड्यूटी पूरी कर अपने चचेरे भाई के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार 'बोलेरो' ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना प्रभारी ने बताया, पहली मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद बोलेरो चालक मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका वाहन आगे चल रही दूसरी मोटरसाइकिल से भी जा टकराया। इस हादसे में दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार दूसरी मोटरसाइकिल पर दिनेश रोत और संदीप (29) सवार थे। चारों घायलों को तत्काल डूंगरपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने धूलसिंह और दिनेश को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस का कहना है कि गंभीर रूप से घायल महिपाल सिंह को बेहतर उपचार के लिए उदयपुर ले जाने की सलाह दी गयी लेकिन लेकिन उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई। संदीप का डूंगरपुर के अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं।

विलुप्ति के कगार पर मालवी ऊंट, बचाने की शुरू हुई वैज्ञानिक मुहिम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। भारत में मान्यता प्राप्त ऊंटों की नौ नस्लों में शामिल दुर्लभ मालवी (सफेद) ऊंट विलुप्त होने के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। इस नस्ल के अब केवल 102 ऊंट ही शेष बचे हैं, जिसे बचाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसी) ने विशेष संरक्षण एवं प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

वर्ष 2019 की पशुधन गणना के अनुसार, मालवी ऊंटों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है, जिसके कारण यह नस्ल संकटग्रस्त श्रेणी में पहुंच गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार, किसी भी ऊंट की नस्ल में यदि प्रजनन योग्य मादा ऊंटों की संख्या 300 से कम रह जाती है, तो उसे विलुप्त होने के खतरे वाली नस्ल माना जाता है। मालवी के अलावा मेवाड़ी और मेवाती नस्ल भी इसी श्रेणी में आती हैं।

इस संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसी) ने विशेष प्रजनन एवं संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। एनआरसीसी के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वेद प्रकाश ने कहा, हमने तीन नर और नौ मादाओं सहित 12 मालवी ऊंट खरीदे हैं तथा उनकी संख्या बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि संस्थान इस नस्ल की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए शुद्ध प्रजनन तकनीक पर काम कर रहा है, ताकि इसकी संख्या बढ़ाई जा सके। मालवी ऊंट अपनी विशिष्ट सफेद रंगत के लिए जाना जाता है और इसे भारत की ऊंट नस्लों में

सबसे छोटा माना जाता है। यह नस्ल दुग्ध उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक मादा मालवी ऊंट एक दुग्ध चक्र में लगभग चार से पांच किलोग्राम दूध देती है।

परंपरागत रूप से इस नस्ल का उपयोग परिवहन और सामान ढोने के लिए किया जाता रहा है। यह मुख्य रूप से मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के मंदसौर, नीमच, रतलाम और ग्वालियर जिलों के अलावा राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में पाई जाती है।

अधिकारियों के अनुसार, बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा ऊंटों की घटती उपयोगिता के कारण इस नस्ल की संख्या लगातार कम होती गई है।

डॉ. वेद प्रकाश ने कहा, संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम के साथ-साथ हम इस नस्ल की विशिष्ट विशेषताओं का अध्ययन भी कर रहे हैं तथा किसानों और पशुपालकों के बीच जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीएजीआर), करनाल की नेटवर्क परियोजना के तहत संचालित किया जा रहा है। इसके तहत पशुपालकों को इस नस्ल की उपयोगिता के बारे में जागरूक किया जा रहा है और इसके संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार वैज्ञानिक प्रयासों और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से ही इस अनूठी रेगिस्तानी धरोहर को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है।

एक करोड़ लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य, 'सुधा' को बनाएंगे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड : मुख्यमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन एक करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन हासिल करना है।

चौधरी ने कहा कि इसके लिए पशुपालकों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण, उन्नत नस्ल के पशु, पशु स्वास्थ्य सुविधाएं और मजबूत डेयरी अवसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, सम्राट चौधरी ने नालंदा के बिहारशरीफ डेयरी परियोजना परिसर में प्रतिदिन 20 टन क्षमता वाले दही एवं लस्सी संयंत्र, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ लिमिटेड (कॉम्फेड) द्वारा संचालित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के पेट्रोल पंप तथा सुधा कैफेटेरिया का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 300 खुदरा विक्रेताओं को डीप फ्रीजर वितरित किए। उन्होंने पशु बचाव एवं परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने बिहारशरीफ स्थित सुधा डेयरी संयंत्र का निरीक्षण भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 टन प्रतिदिन क्षमता वाले दही एवं लस्सी संयंत्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक महासंघ का गठन किया जाएगा। बकरी के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन की व्यवस्था इस महासंघ के माध्यम से विकसित की जाएगी। इससे बकरी पालन से जुड़े लाखों ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और दुग्ध क्षेत्र का दायरा भी बढ़ेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि नालंदा को बिहार का प्रमुख दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा।

आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों, शीत श्रृंखला, विपणन नेटवर्क और नई परियोजनाओं के माध्यम से इसे डेयरी उद्योग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मनुष्यों के साथ-साथ पशुओं के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रही है। दुर्घटना में घायल होने वाले पशुओं को पशु बचाव एवं परिवहन वाहनों के माध्यम से शीघ्र उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में प्रधानमंत्री पशु जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि पशुपालकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण पशु औषधियां उपलब्ध हो सकें। इसके लिए राज्यभर में करीब 1,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल बिहार में दूध एवं दुग्ध उत्पादों की मांग को पूरा करना नहीं, बल्कि 'सुधा' ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक, मूल्य संवर्धन और निर्यात क्षमता को बढ़ाकर बिहार के दुग्ध उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाएगा।उन्होंने कहा कि भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। राज्य में 2,500 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

हर समस्या का उचित और निष्पक्षता से कराएंगे समाधान : मुख्यमंत्री योगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' में आए फरियादियों को भरोसा दिया कि हर समस्या का उचित और निष्पक्षता से समाधान किया जाएगा।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, योगी ने सोमवार सुबह 'जनता दर्शन' के दौरान विभिन्न जिलों से आए प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यहां आए लोगों से कहा कि आप परेशान कतई न हों, सरकार हर समस्या का निष्पक्ष समाधान कराएगी। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए।

बयान के अनुसार, अपराध व जमीन पर कब्जा किए जाने संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

पूर्व जद(यू) सांसद अर्जुन राय भाजपा में शामिल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व सांसद अर्जुन राय सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। राय ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी का विरोध करते हुए करीब एक दशक पहले जद(यू) से नाता तोड़ लिया था। राय ने 2024 का लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर सीतामढ़ी निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था।

उन्होंने अपने कई समर्थकों के साथ भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राय दिवंगत शरद यादव के करीबी माने जाते थे। शरद यादव जद(यू) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वर्ष 2013 तक राजग के संयोजक भी रहे। उसी वर्ष नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया था। इसके चार वर्ष बाद, जब नीतीश ने राजद-कांग्रेस गठबंधन से नाता तोड़कर फिर से भाजपा के साथ सरकार बनाई, तब राय उन चुनिंदा जद(यू) नेताओं में शामिल थे जिन्होंने शरद यादव का साथ देते हुए इस फैसले का विरोध किया और लोकत्रांतिक जनता दल (एलजेडी) का गठन किया। बाद में, वर्ष 2022 में एलजेडी का जद(यू) में विलय हो गया।

डीपफेक, एआई-जनित पोस्ट मामले में गडकरी को मेटा, एक्स और अन्य पर मुकदमा करने की अदालत की मंजूरी

मुंबई/भाषा। बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उनके खिलाफ अपलोड किए गए मानहानिकारक'' डीपफेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-जनित पोस्ट को लेकर मेटा मंच, एक्स कॉर्प, गूगल एलएलसी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दीवानी वाद दायर करने की सोमवार को अनुमति दे दी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता गडकरी ने 'लेटर्स पेटेंट' के खंड-12 के तहत अनुमति याचिका दायर की थी। यह एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, जिसके तहत यदि किसी वाद का कारण उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर उत्पन्न होता है, तो मुकदमा दायर करने से पहले अदालत से अनुमति लेना जरूरी होता है। ऐसी अनुमति आवश्यक होती है, ताकि अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के बावजूद अदालत मुकदमे की सुनवाई कर सके और उसपर फैसला दे सके। न्यायमूर्ति अभय आहूजा की एकल पीठ के समक्ष सोमवार को गडकरी की अनुमति याचिका पर सुनवाई हुई। गडकरी के वकील संदीप लड्डा ने दलील दी कि ऑनलाइन मंचों ने कथित मानहानिकारक और डीपफेक सामग्री महाराष्ट्र के उपयोगकर्ताओं सहित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करायी।

'नबान्न' पर लगी नाम पट्टिका का रंग नीले से बदलकर भगवा किया गया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोलकाता/भाषा। पश्चिम बंगाल सरकार के सचिवालय भवन 'नबान्न' के ऊपर लगी नाम पट्टिका का रंग नीले से बदलकर अब भगवा कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनने के बाद हो रहे बदलावों में से यह एक है। यह बदलाव सोमवार सुबह तब दिखाई दिया, जब हावड़ा स्थित 14 मंजिला प्रशासनिक मुख्यालय 'नबान्न' पर लगा प्रकाशमान साइनबोर्ड नीले रंग की जगह भगवा रंग में नजर आया। हालांकि, इमारत का बाहरी हिस्सा अभी भी नीले और सफेद रंग का ही है।

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''नबान्न की नाम पट्टिका का रंग बदलना, अलग-अलग सरकारी इमारतों में चल रहे रखरखाव और सजावट के काम का ही एक हिस्सा है।'' उन्होंने कहा, ''पूरी नबान्न इमारत को दोबारा रंगने के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।'' अधिकारियों ने बताया कि राज्य सचिवालय की इमारत का रंग पूरी तरह बदलने के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। राज्य में भाजपा की सरकार आने के कुछ ही समय बाद, नबान्न सभागार का रंग भी इसी तरह बदला गया था। नई भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही सचिवालय की इमारत की सजावटी रोशनी और राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी भगवा रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान सरकारी इमारतों, उद्यानों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की पहचान नीले और सफेद रंग बन गए थे।

रांची में 16 माओवादी करेंगे आत्मसमर्पण

रांची/भाषा। झारखंड में 15 लाख रुपये के इनामी नक्सली संतोष उर्फ वासुदेव दा उर्फ दिलीप समेत 16 माओवादी मंगलवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। झारखंड पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आत्मसमर्पण करने वाले 16 माओवादियों में से छह पर कुल 39 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इनमें एक क्षेत्रीय समिति का सदस्य, एक जोनल कमेटी का सदस्य, दो सब-जोनल कमेटी के सदस्य और दो एरिया कमेटी के सदस्य शामिल हैं। इस समूह में कई महिला माओवादी भी शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा-माओवादी) की क्षेत्रीय समिति के सदस्य संतोष का आत्मसमर्पण एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। वह विभिन्न जिलों के थानों में दर्ज 128 मामलों में वांछित था और उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इस अवसर पर भाकपा (माओवादी) की जोनल कमेटी का सदस्य चंदन लोहरा भी आत्मसमर्पण करेगा, जो 78 मामलों में वांछित था और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम था। आत्मसमर्पण के दौरान माओवादी अपने हथियार भी पुलिस को सौंपेंगे, जिनमें छह इंसास रायफल, दो एके-47, एक एचके-33, एक यूएस कार्बाइन और एक एम-16 रायफल के साथ-साथ 38 मैगजीन और 1,562 कारतूस शामिल हैं। हथियार डालने वाले अन्य प्रमुख माओवादियों में सब-जोनल कमेटी के सदस्य अनिल तुरी उर्फ उज्ज्वल और सुखलाल बिरजिया उर्फ अकेला (दोनों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम), एरिया कमेटी के सदस्य सुदेश होनहागा उर्फ सोनाराम होनहागा और रिसिव (दोनों पर 2-2 लाख रुपये का इनाम), तथा जोनल कमेटी का सदस्य संतोष मांझी उर्फ जगबंधु शामिल हैं।

शुभेंदु ने सिक्किम में सुरंग हादसे में मारे गए 11 मज़दूरों के परिवारों को वित्तीय मदद दी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जलपाईगुड़ी/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पड़ोसी राज्य सिक्किम के नामची जिले में हाल ही में सुरंग ढहने की घटना में मारे गए राज्य के 11 प्रवासी मजदूरों के परिवारों को सोमवार को आर्थिक सहायता सौंपी और नौ पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने जलपाईगुड़ी जिलाधिकारी कार्यालय में प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रभावित सभी 11 परिवारों को कुल 21-21 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, आज हमने जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक मदद दी है। नौ परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इनमें से सात को होम गार्ड के तौर पर और दो को नागरिक स्वयंसेवक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। दुख की इस घड़ी में हम इन परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं। अधिकारी ने खुद पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मदद सौंपी।

इनमें से कई लोग मालबाज़ार और उत्तर बंगाल के दूसरे इलाकों से आए थे। उन्होंने मारे गए कर्मचारियों के माता-पिता, जीवनसाथी और भाई-बहनों से भी बातचीत की।

उन्होंने कहा, ''यह कोई परमार्थ का कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से हर शोक संतप्त परिवार को पांच लाख रुपये दे रही है। सिक्किम सरकार पहले ही प्रत्येक परिवार को चार-चार लाख रुपये दे चुकी है।

परियोजना में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हर परिवार को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवज़ा दे रही है, जबकि काम कराने वाला निजी ठेकेदार भी हर परिवार को पांच-पांच लाख रुपये दे रहा है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।''

पिछले हफ्ते नामची में बन रही एक सुरंग का कुछ हिस्सा ढहने से राज्य के 11 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में से नौ जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार के रहने वाले थे।

बिहार में छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 के इस्तेमाल के आरोप में कांस्टेबल निलंबित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार के सीवान जिले में 25 जुलाई को छात्र आंदोलन के दौरान कथित तौर पर एके-47 राइफल का इस्तेमाल करने वाले पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर एक वीडियो के प्रसारित होने के बाद हुई है जिसमें पुलिस कांस्टेबल छात्र प्रदर्शन के दौरान एके-47 राइफल का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। हालांकि, 'पीटीआई-भाषा' इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। सीवान के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पूरण कुमार झा ने कहा, वीडियो में दिखाई दे रहा कांस्टेबल जिला आसूचना इकाई (डीआईयू) में तैनात है जिसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हालांकि, उन्होंने कांस्टेबल की पहचान जारी नहीं की है।

झा ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि प्रदर्शन के दौरान कांस्टेबल ने किन परिस्थितियों में एके-47 राइफल का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को गोली नहीं चलाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

बिहार में पुलिस ने एके-47 चलाई, क्या विद्यार्थी आतंकवादी हैं : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने बिहार के सीवान में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ एक पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर एके-47 का इस्तेमाल किए जाने को लेकर सोमवार को भाजपा पर 'बर्बरता' का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या अब भाजपा की सरकारों में विद्यार्थी ''आतंकवादी'' हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कांस्टेबल एके-47 राइफल का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। हालांकि, 'पीटीआई-भाषा' इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता।

सीवान के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पूरण कुमार झा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''वीडियो में दिखाई दे रहा कांस्टेबल जिला आसूचना इकाई (डीआईयू) में तैनात है, जिसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।'' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर एके-47 से गोली चलाए जाने और सैकड़ों विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया, ''कहां गया आपका वादा कि विद्यार्थियों पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा?'' कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इसके विपरीत विद्यार्थियों पर घातक हमले और ''बर्बरता'' की जा रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में विद्यार्थियों पर 'पैलेट' गन का और बिहार में एके-47 का इस्तेमाल किया गया। गांधी ने कहा, ''मोदी जी, देश के विद्यार्थियों से माफ़ी मांगिए और जिन्होंने विद्यार्थियों हमला किया है, उन्हें कुचला है, उनपर कार्रवाई कीजिए, न कि विद्यार्थियों पर।'' एके-47 राइफलों के इस्तेमाल की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी आतंकवादी नहीं हैं।

सिवान छात्र प्रदर्शन में एके-47 के कथित इस्तेमाल की न्यायिक जांच हो : तेजस्वी

पटना/भाषा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सिवान में 25 जुलाई को छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एके-47 राइफल के इस्तेमाल की सोमवार को न्यायिक जांच कराने की मांग की। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीट प्रश्नपत्र लीक के कथित मामले को लेकर 25 जुलाई को आयोजित बिहार बंद के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की भी मांग की।

उन्होंने सरकार से सोमवार रात तक सभी छात्रों को रिहा करने का आग्रह करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर उनकी पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। तेजस्वी ने कहा, ''सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एके-47 राइफल का इस्तेमाल करने वाले आरक्षी को केवल निलंबित कर देना पर्याप्त नहीं है। इस घटना की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। एके-47 के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया, इसकी पहचान कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। देश में यह पहली बार है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर एके-47 का इस्तेमाल किया गया है।''

छात्रों के ख़िलाफ एके-47 का इस्तेमाल व लाठीचार्ज गलत, हम इसके ख़िलाफ हैं : लोजपा (राम विलास) सांसद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) की सांसद शाम्भवी चौधरी ने बिहार में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एके-47 राइफल के इस्तेमाल और देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज को सोमवार को गलत बताते हुए कहा, ''हम इसके ख़िलाफ हैं।''

उन्होंने कहा कि ''कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि प्रदर्शनों के दौरान असामाजिक तत्व मौजूद थे और कानून-व्यवस्था कायम रखी गई।'' चौधरी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि आप शांति से अपनी बात रख सकते हैं। शांतिपूर्ण विरोध का हमेशा स्वागत है, और हमारे लोकतंत्र में युवाओं को इसमें शामिल होने और अपनी बात रखने का अधिकार है।''

उन्होंने कहा, जहां कहीं एके-47 का इस्तेमाल हुआ है, वह गलत है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं; विभिन्न स्थानों पर छात्रों पर लाठीचार्ज भी गलत है। हालांकि, सोनम वांगचुक और कॉजपा प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया है कि कई मौकों पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान असामाजिक तत्व मौजूद थे, और वहां कानून-व्यवस्था कायम रखी गई।''

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई : उप्र सरकार ने न्यायालय को बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में चार सदस्यों वाली एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) बनाई है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार से एसआईटी में पांचवें सदस्य के तौर पर एक 'फॉरेंसिक ऑडिटर' शामिल करने को कहा, जो दो हफ़्ते के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट सौंपेगी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर किया। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के सुझाव के बाद 25 जुलाई को जारी एक अधिसूचना के ज़रिए एसआईटी का गठन किया गया है। विधि अधिकारी ने कहा कि एसआईटी में पुलिस महानिरीक्षक के अलावा, उपमहानिरीक्षक रैंक के एक अधिकारी, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे। पीठ ने कहा कि एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देने दें। इसने सुनवाई दो हफ़्ते के लिए टालते हुए कहा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे।

राम मंदिर दान चोरी के आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ाई गई

अयोध्या/भाषा। राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले के सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक स्थानीय विशेष अदालत ने सोमवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। बचाव पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी। बचाव पक्ष के वकील कुल शेखर सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक) रजत वर्मा ने आरोपियों को जिला जेल से वस्तुतः अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ा दी। ये आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू हैं। पुलिस जांच के तहत उनसे पुलिस हिरासत के दौरान पूछताछ कर चुकी है।

सुविचार

दया और करुणा मानवता की पहचान हैं। जरूरतमंद की मदद करें, दुखियों का सहारा बनें, यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा धर्म है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

क्रांति या भ्रांति?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर जिस कथित जेन जी क्रांति की बातें हो रही हैं, उसके खतरनाक संकेतों को नज़रअंदाज़ करना भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। कुछ यूट्यूबरों को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापकों में तारणहार मिल गया है। उन्हें लगता है कि ये हर समस्या का समाधान कर देंगे। कुछ ऐसी ही हवा अन्ना आंदोलन के बाद बह रही थी, जब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को देखकर बहुत लोग यह शर्त लगाते थे कि एक बार इनकी सरकार बनने दीजिए, फिर तो दिल्ली की तस्वीर और तकदीर, दोनों बदल जाएंगी! उसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली और पंजाब में सरकारें बनाईं। वर्तमान में पंजाब में उसी की सरकार है। क्या वहां महंगाई, बेरोजगारी, नशाखोरी, सरकारी स्कूलों व अस्पतालों की खस्ता हालत, भ्रष्टाचार और प्रदूषण जैसी समस्याएं नहीं हैं? 'आप' के कई वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। जब सरकारें समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती हैं, उनकी कार्यशैली से लोगों को परेशानी होने लगती है, तब क्रोध और कुंठा का जन्म होता है। ऐसे समय में कुछ लोग आगे आते हैं। भारत की जनता उनसे ज्यादा ही उम्मीदें लगा लेती है। कालांतर में जब उम्मीदें टूटती हैं तो गहरा पछतावा होता है। याद करें, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन हुआ था तो बिहार में कितने युवा नेता उभरे थे? वे महाविद्यालयों से निकले ही थे। लोगों को विश्वास हो चला था कि ये सबकुछ ठीक कर देंगे। बाद में, उनमें से कई नेता कांग्रेस के साथ चले गए। एक महाशय तो कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगलराज के प्रतीक बन गए थे। उन्हें आज भी घोटालों के लिए याद किया जाता है। इसलिए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो चेहरे चर्चा में आए, उन्हें अपना आदर्श बनाने में जल्दबाजी न करें। खासकर युवाओं को इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अनुभव कम है। उन पर भावनाएं जल्दी हावी हो जाती हैं।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भगवान श्रीराम और देवी-देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई थीं। कई लोगों ने खुद को आधुनिक दिखाने के लिए आपत्तिजनक नारे लगाए थे। वे अनुचित संकेत करते दिखाई दिए थे। किसी क्रांतिकारी के लिए चरित्र की पवित्रता पहली शर्त होती है। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों का चरित्र भी महान था। जब प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर जा रहे थे तो कई लोगों के हाथों में ऐसे प्लेकार्ड थे, जिन्हें कोई विवेकशील व्यक्ति अपने परिवार को कभी नहीं दिखा सकता है। एक प्लेकार्ड खूब चर्चा में रहा, जिसमें श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक को मजाकिया ढंग से पेश किया गया था। इस प्रदर्शन में मुस्लिम, सिक्ख और ईसाई समुदाय के लोगों ने भी भाग लिया था। वे अपने धर्म के बारे में और किसी अन्य धर्म के बारे में कोई गलत टीका-टिप्पणी नहीं कर रहे थे। यह अच्छी बात है, लेकिन हिंदू युवा ही हिंदू धर्म के अवतारों और पूजनीय प्रतीकों का मजाक उड़ा रहे थे। ये लोग सरकार का विरोध करते-करते हिंदू धर्म को निशाना बनाने लगे थे। क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए? इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि सरकार को जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। हर नागरिक को उसका जायज हक मिलना चाहिए। किसी ने गलत किया है तो पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। अगर मंत्री के इस्तीफे में हर समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो उसके असर बहुत गहरे होंगे। कल्पना करें, किसी राज्य सरकार के शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा का पेपर दूर-दराज के स्कूल में एक कर्मचारी ने लीक कर दिया। अब क्या होगा? गलती कर्मचारी की थी, लेकिन शिक्षा मंत्री की कुर्सी जाएगी। फिर यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। जिन राज्यों में कांग्रेस और अन्य (विपक्षी) दलों की सरकारें हैं, वहां कोई गड़बड़ हुई तो भाजपा भी संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे मांगेगी। क्या वे मंत्री कुर्सी छोड़ेंगे? क्या सीजेपी उनके खिलाफ आंदोलन करेगी? इसका जवाब देना चाहिए।

ट्वीटर टॉक

छात्रों पर हो रही बेरहमी और पुलिस की ताकत के गलत इस्तेमाल की जो खबरें आ रही हैं, वे बहुत चिंताजनक हैं।ङ्गङ्गबोलने की आज़ादी हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने और उन्हें कुचलने की कोई भी कोशिश डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ है।

-सचिन पायलट

आज मुख्यमंत्री के घर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर श्री रथींद्र बोस जी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी सदाबहार रचना 'गीतांजलि' भेंट की।

-भजनलाल शर्मा

भारतीय दर्शन और सनातन संस्कृति में, गुरु को साक्षात परम ब्रह्म माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का पवित्र त्योहार हम सभी के लिए अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा, आभार और सम्मान दिखाने का मौका है।गुरु सिर्फ़ शिक्षा ही नहीं देते; वे जीवन को रास्ता भी दिखाते हैं।

-योगी आदित्यनाथ

प्रेरक प्रसंग

सफाई से जीवन रक्षा

सन 1847 में वियना के एक अस्पताल में डॉ. इग्नाज़ सेमेल्वाइस कार्यरत थे। उन्होंने एक विचित्र बात पर ध्यान दिया। जिस प्रसूति वार्ड में डॉक्टर प्रसव कराते थे, वहां माताओं की मृत्यु दर दूसरे वार्ड की तुलना में कहीं अधिक थी, जहां दाइयां प्रसव कराती थीं। उन्होंने कई महीनों तक कारण खोजा। अंततः उन्होंने देखा कि डॉक्टर शव-परीक्षण करने के तुरंत बाद बिना हाथ अच्छी तरह साफ किए प्रसूति कक्ष में चले जाते थे। सेमेल्वाइस ने सभी डॉक्टरों के लिए क्लोरीन मिले घोल से हाथ धोना अनिवार्य कर दिया। कुछ ही महीनों में मृत्यु दर नाटकीय रूप से घट गई। उन्हें लगा कि अब सब लोग इस व्यवस्था को अपनाएंगे। लेकिन वरिष्ठ चिकित्सकों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। सेमेल्वाइस के पास आंकड़े थे, परिणाम थे, फिर भी उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने अपना काम जारी रखा। वर्षों बाद विज्ञान ने सिद्ध किया कि वे सही थे। रोगाणुओं के सिद्धांत के विकसित होने पर दुनिया ने समझा कि हाथ धोना केवल सफाई नहीं, जीवन बचाने का उपाय है। आज अस्पतालों में हाथ धोना सामान्य नियम है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस साधारण आदत के पीछे एक ऐसे चिकित्सक का संघर्ष छिपा है।

सामयिक

पंजाब चुनाव में कांग्रेस की राह आसान नहीं !

डॉ. आशीष वशिष्ठ

पंजाब में 'मिशन 2027' का मतलब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग होगा। सत्ताधारी आप के लिए, यह उस इकलौते राज्य को बचाने की 'करो या मरो' वाली लड़ाई है जहां उसकी सरकार है। कांग्रेस के लिए, यह 2022 में खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने की लड़ाई है। शिरोमणि अकाली दल के लिए, यह शायद अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। और आखिर में, भाजपा के लिए, यह अपनी झोली में एक नया राज्य जोड़ने की कोशिश है। कांग्रेस की बात करें तो, पंजाब में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी की राह वाकई आसान नहीं है। पार्टी इस समय अंदरूनी गुटबाजी, नेतृत्व के संकट और मजबूत विपक्ष जैसी कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल की यह घोषणा कि कांग्रेस राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ेगी, इस बात को परोक्ष रूप से स्वीकार करना है कि राज्य इकाई के भीतर चल रही आपसी कलह के खत्म होने की संभावना कम है। यह इस सच्चाई को भी दर्शाता है कि राज्य-स्तर के किसी एक नेता की अगुवाई में एकजुट चुनावी अभियान चलाना राज्य कांग्रेस और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, दोनों की ही क्षमता से बाहर है।

पंजाब की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। कांग्रेस हाईकमान जट्ट सिख (राजा वारिंग) और दलित (चरणजीत सिंह चन्नी) चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों नेताओं के समर्थक अपने नेता को ही मुख्य चेहरा बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी न मिलने से पार्टी के भीतर असंतोष और गहरा गया है। असल में चन्नी को लेकर कांग्रेस आलाकमान की दुविधा दिखती है, वो 2022 को नहीं दोहराना चाहते हैं। जब चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। दूसरा चन्नी पर केंद्रीय एजेंसियों का भी शिकंजा है खासकर कर ईडी का मामला। कुछ इन्हीं वजहों से कांग्रेस नेतृत्व चन्नी को आगे लाने से हिचक रहा है। यहां पर भरोसे का मामला बनता दिख रहा है।

असल में, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बिना किसी सम्मानजनक तरीके के कैप्टन से लीडरशिप छीनकर, राज्य इकाई को उस एकमात्र नेता से वंचित कर दिया, जिनका पूरे राज्य में राजनीतिक प्रभाव था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद से कांग्रेस पंजाब में कोई ऐसा सर्वमान्य और मजबूत 'कैप्टन' खड़ा नहीं कर पाई है जो पूरी पार्टी को एकजुट रखकर चुनावी नैया पार लगा सके। फिलहाल, राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा या प्रताप सिंह बाजवा- इनमें से किसी भी नेता का जनाधार कुछ ही विधानसभा क्षेत्रों से आगे नहीं है, और न ही उनमें से कोई अपने प्रशासनिक दबदबे के लिए जाना जाता है; साफ-सुथरी राजनीतिक छवि की तो बात ही छोड़ दें।

बघेल के बयान से यह साफ है कि वह यह काम करने में नाकाम रहे। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ़ एक ही चेहरा है, और वह हैं राहुल गांधी। राज्य कांग्रेस उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि, इस घोषणा का मतलब यह भी है कि पार्टी नेताओं की रणनीति का मुख्य फोकस चुनाव जीतने पर होना चाहिए। अगला मुख्यमंत्री या विपक्ष का नेता कौन बनेगा, यह चुनाव के नतीजे आने के बाद ही तय होगा। यह रणनीति अपने आप में बुरी नहीं है। भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इसी रणनीति का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। हरियाणा का उदाहरण भी हमारे सामने है। वहां, 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले, मौजूदा सरकार से मतदाताओं की नाराजगी को कम करने की कोशिश में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को लाया गया। यह रणनीति दो मोर्चों पर कारगर साबित हुई। भाजपा ने न केवल लगातार तीसरी बार हरियाणा विधानसभा चुनाव जीता, बल्कि इस कामयाबी ने नायब सिंह का राजनीतिक कद भी बढ़ाया। अब वे पगड़ी पहनकर पंजाब के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों का नियमित दौरा कर रहे हैं और सैनी समुदाय के वोटों को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

राहुल गांधी का नाम लेकर बघेल ने जो कदम उठाया है, उसकी असलियत विधानसभा चुनावों के दौरान ही पता चलेगी। इस नजरिए की एक अहम वजह यह है कि वोट खींचने के मामले में, राहुल गांधी अब तक पूरे देश में भाजपा के नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने में कामयाब नहीं रहे हैं, और न ही निकट भविष्य में ऐसी कामयाबी की कोई उम्मीद है। वैसे भी, पंजाब के हालात अलग हैं। यहां मोदी के समर्थकों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि भाजपा अपने दम पर दो से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत सके, भले ही हालात उसके लिए बहुत अच्छे हों। इसी तरह, नेहरू-गांधी परिवार के समर्थक भी पंजाब के लोगों में उस परिवार के प्रति मौजूद बेरुखी से इनकार नहीं कर सकते। इन सब के बीच कांग्रेस और आप, दोनों को ही भाजपा की चौंकाने वाले नतीजे देने की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। भगवा पार्टी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में ऐसा पहले भी किया है। असलियत यह है कि पंजाब कांग्रेस ने 2002 और 2017 के विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण जीते। लोगों ने कैप्टन में प्रकाश सिंह बादल का विकल्प देखा। असल में, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिन भी निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां कीं, वहां कांग्रेस उम्मीदवार को जीत के बजाय हार का सामना करना पड़ा। 2017 में 77 सीटें जीतने वाली यह पुरानी पार्टी 2022 में सिमटकर 18 सीटों पर आ गई, लेकिन पिछले चार साल का ज्यादातर समय उसने अंदरूनी कलह और नेतृत्व को लेकर उलझन से निपटने में ही बिताया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने से पैदा हुए नेतृत्व के खालीपन को भरने के लिए पार्टी के नेता अभी भी एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले हाईकमान द्वारा हटाए जाने तक अमरिंदर पंजाब कांग्रेस के निर्विवाद नेता थे। वर्ष 2022 से पहले अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई लड़ाई का फायदा उठाने वाले और मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी की कमान संभालने वाले चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी की शर्मनाक हार के बाद से ही लगभग निष्क्रिय रहे हैं। असल में, चन्नी खुद उन दोनों सीटों पर चुनाव हार गए थे जिनसे वे लड़े थे। कांग्रेस हाईकमान ने, जैसा कि वह अक्सर करता है, लंबे समय तक राज्य के नेतृत्व पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया। वर्तमान में सत्तारूढ़ 'आप' सरकार अपनी योजनाओं, मुफ्त बिजली और नौकरियों के दम पर दोबारा सत्ता में लौटने के लिए पूरा जोर लगा रही है, जिससे पार पाना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है।

वहीं पश्चिम बंगाल में मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा भी पूरे उत्साह के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी है। शिरोमणि अकाली दल भी अपनी खोयी राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिशों में जुटा है। विपक्ष कांग्रेस की इसी कुर्सी की जंग और गुटबाजी पर लगातार तंज कस रहे हैं, जिससे जनता के बीच पार्टी की छवि प्रभावित हो रही है। ऐसे में, यह आसानी से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी का नेतृत्व विधानसभा चुनावों में राज्य कांग्रेस को किस हद तक सफलता दिला पाएगा। यदि कांग्रेस को 2027 के चुनावों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पानी है, तो केंद्रीय नेतृत्व को जल्द से जल्द पंजाब इकाई के मतभेदों को सुलझाना होगा। जब तक पार्टी एकजुट होकर जमीन पर नहीं उतरती, तब तक पंजाब में उसकी राह बेहद चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी।

नजरिया

परिवार परम्परा एवं बिखरते रिश्ते पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

परिवार केवल एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग, धैर्य और संस्कारों का जीवंत विद्यालय है। जब इस विद्यालय की नींव कमजोर होने लगती है तो उसका प्रभाव केवल एक घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा समाज उसकी कीमत चुकाता है। देश के बहुचर्चित सोनम रघुवंशी 'हनीमून मर्डर' प्रकरण की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा व्यक्त की गई चिंता केवल एक अपराध पर की गई टिप्पणी नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज के बदलते चरित्र का गहन सामाजिक विश्लेषण थी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले ने जिस पीड़ा के साथ कहा कि संयुक्त परिवार लोगों को धैर्य, संयम, सहनशीलता और समायोजन सिखाते थे, वहीं आज एकल परिवारों में अवसाद, असहिष्णुता और संबंधों का विघटन बढ़ रहा है, वह हमारे समय का कटु सत्य है। माता-पिता और संतान, भाई-बहन, दादा-दादी और पोते-पोतियों के बीच भी भावनात्मक दूरी लगातार बढ़ रही है, यह परिवार परम्परा एवं रिश्तों में बढ़ती दूरी अब पति-पत्नी के बीच भी बड़ी दरारें डालने लगी है। रिश्तों का खोखलापन इतना बढ़ गया है कि अपनी ही पत्नी या पति की हत्या करने में भी तनिक संकोच नहीं रहा। ऐसे घटनाएं बार-बार देखने को मिल रही है। घर बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल छोटे होते जा रहे हैं। सुविधाएं बढ़ी हैं, परंतु संवेदनाएं सिकुड़ती जा रही हैं। संवाद कम हो गए हैं और स्क्रीन का समय बढ़ गया है। परिणामस्वरूप रिश्ते धीरे-धीरे औपचारिकता में बदलते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में विवाह से पहले अथवा विवाह के कुछ ही दिनों बाद हुई इन नृशंस हत्याओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के पतन का संकेत है। जिन परिवारों में धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, वहीं जीवन का सबसे बड़ा अभाव विश्वास और संतोष का था। संत कबीर का यह वचन आज पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है- जब आए संतोष धन, सब धन धूरि समान।' भौतिक संपन्नता कभी भी मानसिक शांति और रिश्तों की ऊष्मा नहीं खरीद सकती।

भारतीय संस्कृति ने परिवार को केवल सामाजिक संस्था नहीं माना, बल्कि धर्म, संस्कृति और जीवन-मूल्यों का प्रथम विद्यालय माना है। संयुक्त परिवार में दादा-दादी केवल बुजुर्ग नहीं होते थे, वे अनुभवों के विश्वविद्यालय होते थे। नाना-नानी केवल रिश्तेदार नहीं, बल्कि संस्कारों के संरक्षक होते थे। बच्चों को कहानियों के माध्यम से धैर्य, करुणा, क्षमा, संयम और त्याग का पाठ पढ़ाया जाता था। घर का हर सदस्य दूसरे के दुःख का सहभागी होता था। इसलिए किसी एक व्यक्ति का तनाव पूरे परिवार की शक्ति से हल्का हो जाता था। आज यह सुरक्षा-कवच तेजी से टूट रहा है। महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में पति-पत्नी दोनों कार्यस्थल पर व्यस्त हैं। बच्चों का बचपन मोबाइल, टैबलेट और घरेलू सहायिकाओं के भरोसे बीत रहा है। जब बच्चा रोता है तो उसे गोद नहीं, मोबाइल थमा दिया जाता है। यह सुविधा का समाधान नहीं, संवेदनाओं का विस्थापन है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि भावनाओं का विकल्प गैजेट्स नहीं हो सकते', हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक चेतावनी है।

डिजिटल क्रांति ने जीवन को सरल अवश्य बनाया है, लेकिन यदि तकनीक मनुष्य पर हावी हो जाए तो वह संबंधों की सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है। आज परिवार एक ही कमरे में बैठकर भी अलग-अलग दुनिया में खोया रहता है। भोजन की मेज पर संवाद समाप्त हो गया है। आंखों में आंखें डालकर बातें करने की परंपरा लुप्त होती जा रही है। इससे भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ रहा है और अकेलापन बढ़ रहा है। इस पूरे संकट की जड़ केवल आधुनिकता नहीं है। समस्या आधुनिकता के असंतुलित और अंधानुकरण में है। पश्चिम से हमने तकनीक तो अपनाई, लेकिन उसकी सामाजिक चुनौतियों से सीख नहीं ली। अब पति और पत्नी के बीच तीसरा आना आम बात हो गयी है, और यही तीसरा समस्या की जड़ है। इस तरह के अवैध रिश्तों ने त्रासद घटनाओं को जन्म दिया है।

भारतीय परिवार व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी-मैं' से पहले हम' का भाव। आज हम' की जगह मैं' ने ले ली है। अधिकारों की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन कर्तव्यों का स्मरण बहुत कम होता है। रिश्तों में बढ़ता अहंकार भी विघटन का बड़ा कारण है। पति-पत्नी दोनों अपने-अपने तर्कों को अंतिम सत्य मानने लगे हैं। कोई झुकना नहीं चाहता। जबकि भारतीय परंपरा ने सिखाया था कि झुकना हार नहीं, बल्कि संबंधों को बचाने की सबसे बड़ी जीत है। क्षमा और संवाद हर टूटते रिश्ते की पहली दवा हैं, किंतु आज संवाद की जगह आरोप और क्षमा की जगह प्रतिशोध ने ले ली है। यह भी विचारणीय है कि आज विवाह को जीवनभर का संस्कार नहीं, बल्कि सुविधानुसार निभाया जाने वाला अनुबंध समझा जाने लगा है। यही कारण है कि छोटी-छोटी असहमतियां भी अदालतों तक पहुंच रही हैं। न्यायालय न्याय दे सकता है, लेकिन प्रेम नहीं लौटा सकता। कानून अधिकारों का संरक्षण कर सकता है, लेकिन आत्मीयता का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए पारिवारिक समस्याओं का स्थायी समाधान न्यायालयों में नहीं, परिवारों के भीतर ही खोजा जाना चाहिए।

भारत आज विश्वगुरु बनने का स्वप्न देख रहा है। आर्थिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धियां, डिजिटल नवाचार और वैश्विक नेतृत्व निश्चित रूप से गर्व के विषय हैं। लेकिन यदि हमारी सबसे बड़ी सांस्कृतिक शक्ति संयुक्त परिवार' कमजोर हो जाएगी, तो यह प्रगति अधूरी रह जाएगी। विश्व भारत से केवल आर्थिक शक्ति की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उन जीवन-मूल्यों की भी अपेक्षा करता है जिन्होंने हजारों वर्षों तक इस सभ्यता को जीवित रखा है। विश्वगुरु वही बन सकता है जो अपने परिवारों को भी मजबूत रख सके। जिस समाज में माता-पिता उपेक्षित हों, बुजुर्ग अकेले हों, बच्चे भावनात्मक रूप से असुरक्षित हों और पति-पत्नी विश्वास के संकट से जूझ रहे हों, वह केवल आर्थिक महाशक्ति बन सकता है, सांस्कृतिक महाशक्ति नहीं।

समय आ गया है कि परिवारों में पुनः संवाद की संस्कृति विकसित की जाए। सप्ताह में कुछ समय ऐसा हो जब पूरा परिवार बिना मोबाइल के साथ बैठे। बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं, अच्छे संस्कार भी मिलें। विद्यालयों में जीवन-मूल्य और भावनात्मक शिक्षा को महत्व दिया जाए। विवाह-पूर्व परामर्श, पारिवारिक परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि परिवार में बुजुर्गों की भूमिका को पुनः सम्मानपूर्वक स्थापित किया जाए, क्योंकि वे केवल अतीत के प्रतीक नहीं, बल्कि भविष्य के मार्गदर्शक हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी किसी न्यायिक टिप्पणी भर नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी का शंखनाद है। यदि हमने अभी भी अपने परिवारों को बचाने का प्रयास नहीं किया तो आने वाले वर्षों में केवल अदालतों में मुकदमे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि समाज की संवेदनाएं भी समाप्त होती जाएंगी।

भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है- वसुधैव कुटुम्बकम।' लेकिन जो समाज अपने ही परिवार को नहीं बचा पाएगा, वह पूरी दुनिया को परिवार कैसे मान सकेगा? आज आवश्यकता नई इमारतें बनाने की नहीं, बल्कि बिखरते घरों को जोड़ने की है। नई तकनीक विकसित करने की नहीं, बल्कि टूटते संवादों को पुनर्जीवित करने की है। नई पीढ़ी को केवल सफल बनाने की नहीं, बल्कि संवेदनशील बनाने की है। यदि भारत को सचमुच विश्वगुरु बनना है, तो उसकी शुरुआत संसद, न्यायालय या विश्वविद्यालयों से नहीं, बल्कि हर घर के आंगन से होगी। संयुक्त परिवार की आत्मा, रिश्तों की गरिमा, संवाद की संस्कृति और संस्कारों की विरासत को पुनर्जीवित करना ही इस युग की सबसे बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता है। यही सुप्रीम कोर्ट की चिंता का वास्तविक संदेश है और यही भारतीय सभ्यता के भविष्य की सबसे बड़ी आशा भी।

भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है- वसुधैव कुटुम्बकम।' लेकिन जो समाज अपने ही परिवार को नहीं बचा पाएगा, वह पूरी दुनिया को परिवार कैसे मान सकेगा? आज आवश्यकता नई इमारतें बनाने की नहीं, बल्कि बिखरते घरों को जोड़ने की है। नई तकनीक विकसित करने की नहीं, बल्कि टूटते संवादों को पुनर्जीवित करने की है। नई पीढ़ी को केवल सफल बनाने की नहीं, बल्कि संवेदनशील बनाने की है। यदि भारत को सचमुच विश्वगुरु बनना है, तो उसकी शुरुआत संसद, न्यायालय या विश्वविद्यालयों से नहीं, बल्कि हर घर के आंगन से होगी।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टैंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

प्रतिस्पर्धा

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 के दौरान सोमवार को पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत के सचिन सिवाच और इंग्लैंड के विलियम हेविट प्रतिस्पर्धा करते हुए।

अब मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं : सानवी तलवार

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री सानवी तलवार इन दिनों अपनी हॉरर थ्रिलर फिल्म 'खामोश आहटें' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि पहले के मुकाबले वे आज अपनी बात को रखने में सहज महसूस करती हैं। अभिनेत्री से आईएएनएस ने पूछा, आपके करियर में एक समय ऐसा भी आया था, जब आप एक निजी विवाद के कारण सुर्खियों में रहीं। उस अनुभव से आपने क्या सीखा? अभिनेत्री सानवी तलवार ने कहा, मैंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा है कि जब आपको सही समय लगे, तभी अपनी राय रखनी चाहिए। पहले मैं सिर्फ सीमित लोगों से बातें किया करती थी, लेकिन अब समझ आता है कि जब कोई बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, तो उसका मतलब बदल जाता है। आज मैं खुलकर अपनी बात रखने में सहज महसूस करती हूं, क्योंकि यह मेरा अपना फैसला है। अब मैं इस बात की चिंता नहीं करती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मुझे लगता है कि कोई बात सही है, तो मुझे उसके बारे में बोलना चाहिए।दरअसल, अभिनेत्री सानवी तलवार ने एक इंटरव्यू के दौरान करण कुंद्रा पर आरोप लगाते हुए बताया था कि 2015 के टीवी शो 'ये कहां आ गए हम' के सेट पर एक सीन के दौरान करण ने डायरेक्टर के एक्शन बोलने से पहले उन्हें जबरन किस किया, जिसके जवाब में सानवी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद करण ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और गाली गलौज की थी।कई लोगों ने सवाल उठाया कि आपने इस मुद्दे पर इतनी देर बाद क्यों बात की। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, जो अपनी बात कहने से झिझकती हैं? अभिनेत्री ने कहा, मैं हर महिला से कहना चाहूंगी कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और आप उस समय अपनी बात नहीं कह पाईं, तो भी कभी देर नहीं होती। जब आपको सही लगे और आप तैयार महसूस करें, तब अपनी बात सामने रखें। अगर आप अपने अनुभवों के बारे में कभी नहीं बोलेंगी, तो लोग सच्चाई जान नहीं पाएंगे। मेरी बात किसी के माध्यम से अनुषा दांडेकर (करण कुंद्रा की एक्स गर्लफ्रेंड) के पास पहुंच गई थी।

मुलाकात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मुंबई स्थित वर्षा बंगले पर नेपाल के सांसद संदीप राणा और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

पंकज त्रिपाठी को आईएफएफएम में मिलेगा 'आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन' पुरस्कार

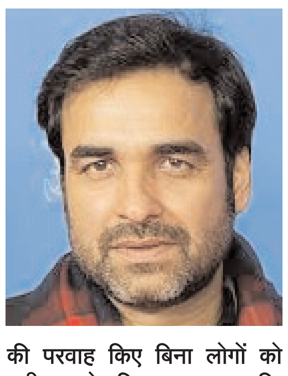

नई दिल्ली/भाषा। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारतीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफएम), 'मेलबर्न में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन' (प्रतिष्ठित कलाकार) पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह सम्मान भारतीय सिनेमा में अभिनेता के असाधारण योगदान और देश के सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक के रूप में उनकी उल्लेखनीय यात्रा को देखते हुए दिया जाएगा। यह पहली बार होगा जब राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता इस फिल्म महोत्सव में शामिल होंगे और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में यह सम्मान प्राप्त करेंगे। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'न्यूटन' और 'स्त्री' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले पंकज त्रिपाठी ने कहा कि यह पुरस्कार मिलना उनके लिए वास्तव में खास और बेहद मायने रखने वाला है।

उन्होंने एक बयान में कहा, भारतीय फिल्म महोत्सव, मेलबर्न में जल्द ही 'आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन' सम्मान प्राप्त करना मेरे लिए बेहद गर्व का क्षण है। एक अभिनेता के तौर पर मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि कहानियों में सीमाओं को पार करने, दिलों को जोड़ने और भाषा या भौगोलिक दूरी की परवाह किए बिना लोगों को करीब लाने की असाधारण शक्ति होती है। उन्होंने कहा, आईएफएफएम जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर मेरी यात्रा को पहचान मिलना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। मेरे करियर की हर उपलब्धि फिल्म निर्माताओं, लेखकों, निर्देशकों, सह-कलाकारों, तकनीशियनों और सबसे बढ़कर दर्शकों के विश्वास और सहयोग से संभव हो पाई है, जिन्होंने मेरे काम को इतना प्यार और अपनापन दिया। यह सम्मान जितना मेरा है, उतना ही उन सभी लोगों का भी है।

उन्होंने कहा, बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाले मेरे जैसे व्यक्ति ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिन कहानियों का मैं हिस्सा बनूंगा, वे एक दिन पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी और इस तरह सराही जाएंगी।

'मुझको राणाजी माफ करना' के नए वर्जन में दिखीं माहिरा शर्मा

मुंबई/एजेन्सी

90 के दशक के कई गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इनमें से एक है फिल्म 'करण अर्जुन' का मशहूर गीत 'मुझको राणाजी माफ करना', जिसने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की थी। अब इस सदाबहार गाने को नए अंदाज में 'राणाजी 2.0' के नाम से पेश किया गया है। नए वर्जन में अभिनेत्री माहिरा शर्मा नजर आ रही हैं। इस पर माहिरा का कहना है कि इतने लोकप्रिय गाने को रीक्रिएट करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि दर्शकों की उम्मीदें पहले से ही बहुत बड़ी थीं। माहिरा शर्मा ने कहा, ''जब आप किसी आइकॉनिक गाने से जुड़ते हैं तो थोड़ा दबाव जरूर होता है, क्योंकि उन गानों से लोगों की पुरानी यादें जुड़ी होती हैं। मेरी कोशिश रही कि मैं अपनी अलग एनर्जी लेकर आऊं, लेकिन गाने की असली पहचान और एहसास को भी बरकरार रखूं।'' उन्होंने कहा, '''राणाजी 2.0' की म्यूजिक, कोरियोग्राफी और वीडियो का पूरा लुक मिलकर एक नया अनुभव देता है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पूरी टीम ने इस गाने को बनाते समय आनंद लिया, उसी तरह दर्शक भी इसे देखकर खूब पसंद करेंगे।''

इस गाने की कोरियोग्राफी मशहूर डांस डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने की है। उन्होंने कहा, ''समय के साथ डांस का अंदाज काफी बदल गया है और यही बात 'राणाजी 2.0' को खास बनाती है। हमारी कोशिश थी कि गाने के विजुअल्स नए और मनोरंजक हों, लेकिन उसकी पुरानी पहचान भी बनी रहे। हम चाहते थे कि जिन्होंने सालों से इस गाने को पसंद किया है और जो पहली बार इसे सुन रहे हैं, दोनों ही इसे देखने का आनंद लें।'' वहीं, संगीतकार तनिष्क बागची ने कहा, ''किसी क्लासिक गाने को नए रूप में तैयार करना आसान नहीं होता। जब किसी पुराने लोकप्रिय गाने पर काम करते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी एहसास को सुरक्षित रखना होता है। इस गाने की धुन और आवाज की अपनी अलग विरासत है। मेरा पूरा ध्यान इसे नया साउंड देने पर था, लेकिन इस तरह कि लोगों को वही पुरानी यादें भी महसूस हों। मैं चाहता था कि यह आज के दौर के हिसाब से भी ताजा लगे और साथ ही लोगों को याद दिलाए कि यह गाना आखिर इतना क्लासिक क्यों बना।'' 'राणाजी 2.0' को टिप्स म्यूजिक ने रिलीज किया है। इस नए वर्जन में इला अरुण और अलका याज्ञनिक की आवाज को बरकरार रखा गया है। यह गाना आधुनिक संगीत और पुराने जादू का मेल बनकर सामने आया है। 'मुझको राणाजी माफ करना' साल 1995 में आई सुपरहिट फिल्म 'करण अर्जुन' का हिस्सा था। इस फिल्म में शाहरुख खान, सलमान खान, राखी, काजोल और ममता कुलकर्णी जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की तरह इसके गाने भी जबरदस्त हिट हुए थे। खास तौर पर ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया यह गीत आज भी 90 के दशक के सबसे यादगार गानों में गिना जाता है।

'फूड फेस्टिवल' में हुई गोलीबारी में तीन लोगों की मौत के बाद पुलिस को दूसरे संदिग्ध की तलाश

सिएटल/एपी। अमेरिका के सिएटल शहर स्थित ऐतिहासिक 'टावर स्पेस नीडल' के पास रविवार शाम आयोजित एक फूड फेस्टिवल' के दौरान गोलीबारी की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और एक बच्चा समेत चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। जांचकर्ताओं का मानना है कि दोनों संदिग्ध रविवार को एक-दूसरे पर गोली चला रहे थे। हालांकि, एक संदिग्ध अब भी फरार है, लेकिन सिएटल पुलिस के सहायक प्रमुख टाइरोन डेविस ने रविवार रात संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है।

डेविस ने बताया कि पुलिस के पास फरार संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, ''हम अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था।'' सोमवार सुबह पुलिस ने फोन और ईमेल के जरिए पूछे गए सवालों का तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। अधिकारियों के अनुसार, दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में 19 और 44 वर्षीय दो पुरुष तथा 56 वर्षीय एक महिला शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दो वर्षीय एक बच्चे सहित चार घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। डेविस ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस घटना में जान गंवाने वाला कोई व्यक्ति गोलीबारी में शामिल था या नहीं।

गोलीबारी रविवार शाम करीब छह बजे तीन दिवसीय वार्षिक 'फूड फेस्टिवल' 'बाइट ऑफ सिएटल' में हुई। इस आयोजन में हर साल खुदरा विक्रेता आदि भाग लेते हैं। डेविस ने बताया कि कार्यक्रम की सुरक्षा में सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात थे और उनमें से कुछ ने एक संदिग्ध को गोली चलाते हुए देखा। उन्होंने बताया कि एक संदिग्ध ने मौके पर ही आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पूरे परिसर में उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस और आपातकालीन सेवा के दल मौके पर पहुंचे और सिएटल सेंटर परिसर तथा आसपास के इलाके को खाली कराया। प्रत्यक्षदर्शी फेथ एडिया हंटर ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ एक विक्रेता से खाना लेकर लौटी ही थीं कि अचानक गोलियां चलने लगीं। उन्होंने बताया कि उन्हें एहसास हुआ कि हमलावर उनके बेहद करीब है, इसके बाद वह और कई अन्य लोग पास स्थित 'सिएटल चिल्ड्रन्स म्यूज़ियम' में जाकर छिप गए। हंटर ने कहा, ''जब गोलीबारी शुरू हुई, वह हमारे (हमलावर) बिल्कुल पास थे, इसलिए हम तुरंत भागने लगे। भीड़ के साथ हम भी दौड़कर इमारत के अंदर चले गए।'' घटना के दौरान अफरा-तफरी मच गई। कई विक्रेता अपने 'फूड स्टॉल' छोड़कर बाहर की ओर भाग गए। कई घंटों बाद भी कुछ विक्रेता पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड के बाहर इस इंतजार में खड़े रहे कि उन्हें अपने टेंट, खाने-पीने की सामग्री और खाना बनाने के उपकरण लेने के लिए कब अंदर जाने दिया जाएगा।

'फूड फेस्टिवल' में स्टॉल लगाने वाले रोबर्टो रामिरेज ने बताया कि ''पहले उन्हें पटाखे जैसी आवाज सुनाई दी। इसके बाद लोगों ने 'शूटर... शूटर' चिल्लाना शुरू कर दिया और हर तरफ भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा, अचानक पूरा इलाका खाली हो गया। लोग बेहद घबरा गए थे।'' उन्होंने कहा, अचानक पूरा इलाका खाली हो गया। लोग बेहद डरे हुए थे। रामिरेज ने बताया कि अफरा-तफरी के बाद भी कई लोग घटना से अनजान होकर महोत्सव में पहुंचते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें तुरंत वहां से लौटने के लिए कह रही थी। 'बाइट ऑफ सिएटल' वार्षिक फूड फेस्टिवल' की शुरुआत 1982 में हुई थी। आयोजकों की वेबसाइट के अनुसार, इस तीन दिवसीय आयोजन में हर वर्ष लगभग साढ़े तीन लाख लोग आते हैं और भोजन, पेय पदार्थों और सामुदायिक उत्सव का आनंद उठाते हैं।

फिल्म 'द ओडिसी' ऑनलाइन लीक हुई

लास एंजिलिस/भाषा। हॉलीवुड स्टूडियो यूनिवर्सल पिक्चर्स ने निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' के ऑनलाइन लीक होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अपनी सामग्री और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए सभी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह फिल्म 17 जुलाई को रिलीज हुई थी। मनोरंजन समाचार वेबसाइट हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार, फिल्म का लीक संस्करण शनिवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किया गया, जिसे 50,000 से अधिक बार देखा गया। बाद में इसे हटाया गया। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने एक बयान में कहा, फिल्म के अनधिकृत रूप से साझा किए जाने की जानकारी मिलते ही हमने उसे हटाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी। हम कॉपीराइट उल्लंघन को गंभीरता से लेते हैं और अपनी सामग्री तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए सभी उचित कानूनी उपाय करेंगे।

उद्घाटन

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सोमवारको सोनारपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक रूपा गांगुली 'सोनारपुर माँ आहार कैंटीन' का उद्घाटन करती हुईं।

फैशन गर्ल मुग्धा गोडसे का सफर, कभी पेट्रोल पंप पर किया काम, आज करोड़ों की मालकिन

मुंबई/एजेन्सी

फैशन इंडस्ट्री और ग्लैमर की दुनिया जितनी चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का सफर उतना ही संघर्षभरा होता है। छोटे शहर से निकलकर रैंप के जरिए देश के सबसे बड़े फैशन प्लेटफॉर्म पर छा जाना और फिर बॉलीवुड की सिल्वर स्क्रीन पर अपनी दमदार अभिनय क्षमता का लोहा मनवाना आसान बात नहीं है। अभिनेत्री मुग्धा गोड्से का सफर इस बात का जीता-जागता उदाहरण है। कहते हैं कि संघर्ष इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अभिनेत्री मुग्धा गोड्से की जिंदगी इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है। भले ही, आज के समय अभिनेत्री किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक वक्त ऐसी भी था, जब उन्हें करियर की शुरुआत में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। 26 जुलाई 1986 को पुणे में जन्मी मुग्धा गोड्से ने अपनी जिंदगी के शुरुआती वर्षों में गुजारा करने के लिए छोटे-मोटे काम किए। कहा जाता है कि गुजर-बसर के लिए अभिनेत्री ने पेट्रोल पंप पर भी काम किया है। एक दौर ऐसा भी था, जब वह पूरे दिन में सिर्फ 100 रुपए ही कमा पाती थीं, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर आज वह करोड़ों की मालकिन हैं।

अभिनेत्री काम करने के साथ-साथ कई स्थानीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया करती थीं। हालांकि, मुग्धा की जिंदगी तब बदली, जब उन्होंने 'ग्लैडरेग्स मेगा मॉडल हंट' में भाग लेकर सफलता हासिल की थी। इसी साल उन्होंने बेस्ट मॉडल और मिस इंडिया में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का खिताब जीत लिया था और साल 2004 के दौरान मुग्धा फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सेमी-फाइनलिस्ट भी रहीं।

इसके बाद मुग्धा ने मधुर भंडारकर की फिल्म 'फैशन' से अभिनय और हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत भी थीं। उनकी पहली ही फिल्म को काफी सराहना मिली और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू आर्टिस्ट के लिए नामांकन मिला और उन्होंने अप्सरा अवॉर्ड जीता।इसके बाद साल 2009 में वह रोहित शेट्टी की कॉमेडी फिल्म 'ऑल द बेस्ट: फन बिगिंस' और मधुर भंडारकर की ड्रामा फिल्म 'जेल' में नजर आईं थी। अपने करियर के दौरान मुग्धा ने हिंदी के अलावा, अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 'हेल्प' (2010), 'गली गली चोर है' (2012), 'हीरोइन' (2012), 'साहेब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स' (2013) और सत्याग्रह (2013) है। उन्होंने मराठी रियलिटी शो 'मराठी पाडते पुढे' में जज की भूमिका भी निभाई थी। हालांकि, ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ-साथ उनका झुकाव अब आध्यात्म और कृष्ण भक्ति की तरफ भी है, जिसे वह अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं

राहुल बोस - अभिनय से मिली पहचान, रग्बी से मिला सम्मान

नई दिल्ली/एजेन्सी

27 जुलाई 1967 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में जन्मे राहुल बोस महज एक कुशल अभिनेता नहीं बल्कि एक पूर्व अंतरराष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी, एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता और एक निस्वार्थ समाज सेवक भी हैं। बचपन में अपनी मां द्वारा बॉक्सिंग और रग्बी से परिचित कराए गए राहुल बोस ने कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और बाद में सिडेनहैम कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। इसी दौरान उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से क्रिकेट का प्रशिक्षण भी लिया और बॉक्सिंग में रजत पदक जीता। उनका असली जुनून रग्बी बना जिसके लिए उन्होंने 1998 से 2009 तक 11 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और अभिनेता के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था। 1994 से 2009 के बीच अपनी 24 फिल्मों की शूटिंग का समय उन्होंने रग्बी कैलेंडर के हिसाब से तय किया।1998 से 2009 तक राहुल बोस ने भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीम के लिए 11 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेला। 2017 में भारतीय महिला रग्बी टीम ने एशिया सेवेंस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। 15 अगस्त 2021 को ओडिशा सरकार ने भारतीय रग्बी टीम की स्पॉन्सरशिप शुरू की। 18 दिसंबर 2021 को राहुल बोस ने रग्बी इंडिया के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला।

राहुल बोस का अभिनय से पहला परिचय मात्र छह साल की उम्र में स्कूल के नाटक 'टॉम, द पाइपर्स सन' में हुआ था। मां के निधन के बाद रेडिफ्यूजन में एक कॉपीराइटर के तौर पर काम करने वाले राहुल बोस ने फिल्म इंग्लिश, ऑगस्ट (1994) की भारी सफलता के बाद पूर्णकालिक अभिनेता बनने का फैसला किया। व्यावसायिक सिनेमा की जगह उन्होंने हमेशा समानांतर सिनेमा को चुना।

मिस्टर एंड मिसेज अय्यर, चमेली, झंकार बीट्स और विश्वरूपम जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। एक निर्देशक के तौर पर उनकी पहली निर्देशित फिल्म एवरीबडी सेज आई एम फाइन! (2001) के लिए फंड जुटाने में उन्हें महज 33 दिन लगे। इसके बाद उन्होंने पूर्णा (2017) का निर्देशन किया, जो 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की की बायोपिक थी। इस फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच की गई थी।

सिनेमा और खेल से परे राहुल बोस एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।

2004 की भीषण सुनामी के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राहत कार्यों ने उनके जीवन को एक नया मकसद दिया। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने 'द फाउंडेशन' की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज से हर प्रकार के भेदभाव को मिटाना है। फाउंडेशन के 'प्रोजेक्ट रीच' के माध्यम से वे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से कटे हुए क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उनके 'प्रोजेक्ट हील' ने बाल यौन शोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 35,000 से अधिक शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को प्रशिक्षित किया है।

जयगोपाल गरोड़िया मेधावी एवं स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 का भव्य आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। श्री अग्रवाल सभा ने अपने प्लैटिनम जुबली वर्ष (75वें स्थापना वर्ष) के उपलक्ष्य में जयगोपाल गरोड़िया मेधावी एवं स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 का आयोजन डी. जी. वैष्णव कॉलेज ऑडिटोरियम, अरुम्बक्कम में सम्पन्न किया। इस अवसर पर समाज के मेधावी विद्यार्थियों एवं उत्कृष्ट खेल प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ वैदिक मंत्रोच्चार, गणेश वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि डॉ. सुनील श्रॉफ, सभा के अध्यक्ष सीताराम गोयल, महासचिव बालगोविंद गुप्ता, प्लैटिनम जुबली चेयरमैन विजय गोयल, जयगोपाल गरोड़िया फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी अशोक केड़िया, मेधावी पुरस्कार समिति के अध्यक्ष संतोष गोयल, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स चेयरमैन योगी सराफ, मेधावी पुरस्कार समिति के सह-अध्यक्ष आशीष गुप्ता एवं सुनीता खेमका द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

अपने स्वागत उद्बोधन में सभा के अध्यक्ष सीताराम गोयल ने सभा की गौरवशाली 75 वर्षों की यात्रा का उल्लेख करते हुए शिक्षा, संस्कार एवं सेवा के क्षेत्र में सभा के अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात प्लैटिनम जुबली चेयरमैन विजय गोयल ने प्लैटिनम जुबली वर्ष के दौरान आयोजित किए जाने वाले विविध कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए सभी से सक्रिय सहभागिता का आग्रह किया।

मुख्य अतिथि डॉ. सुनील श्रॉफ ने विद्यार्थियों से जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ-साथ मानवीय मूल्यों, सेवा-भाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाने का संदेश दिया। समारोह के दौरान जयगोपाल गरोड़िया फाउंडेशन की ओर से समाज के प्रति उनके निरंतर एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री अशोक केड़िया का विशेष सम्मान भी किया गया।

इसके पश्चात मेधावी पुरस्कार समिति के अध्यक्ष संतोष गोयल ने पुरस्कारों का परिचय प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि डॉ. सुनील श्रॉफ के करकमलों द्वारा मेधावी विद्यार्थियों एवं खेल प्रतिभाओं को जयगोपाल गरोड़िया मेधावी एवं स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 प्रदान किए गए। सम्मानित विद्यार्थियों एवं खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों पर सम्पूर्ण सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण प्रसिद्ध एक्सपीरिएंशियल पोएट एवं मोटिवेशनल स्पीकर साहिल अग्रवाल ने अपने जीवन अनुभवों, प्रेरक प्रसंगों एवं भावपूर्ण कविताओं के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके विचारों एवं प्रस्तुति को श्रोताओं ने भरपूर सराहना प्रदान की।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभा के अध्यक्ष सीताराम गोयल एवं महासचिव बालगोविंद गुप्ता ने कुमारी तिया अग्रवाल एवं कुमारी नव्या सराफ को उनके उत्कृष्ट मंच संचालन एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए स्मृति-चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

भ्रमणा का अंत किए बिना आत्मा का भ्रमण समाप्त नहीं हो सकता : पंन्यास ज्ञानबोधि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

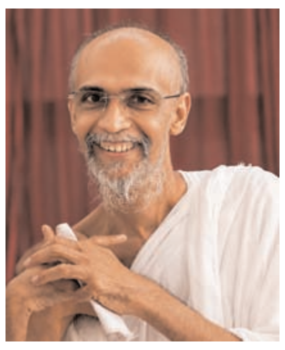

चेन्नई। वेपेरी श्वेताम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ में विराजित आचार्य भगवंत कुलबोधिसूरिश्वरजी म. के शिष्य पंन्यास ज्ञानबोधि विजयजी म. ने गौतम किरण परिसर में आयोजित धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आत्मा के अनादिकालीन भ्रमण का अंत करना है तो सबसे पहले मन की भ्रमणा (भ्रम और मिथ्या धारणा) का अंत करना होगा। जब तक मनुष्य भ्रमणा में जीता रहेगा, तब तक आत्मा का वास्तविक कल्याण संभव नहीं है।

उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के जीवन प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिकांश लोग ऐसे जीवन जीते हैं मानो उन्हें अपने कर्मों का कोई परिणाम स्वयं नहीं भोगना पड़ेगा। हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव केवल दूसरों पर पड़ेगा, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है।

इसलिए आत्मिक यात्रा प्रारंभ करने से पहले भ्रमणा से बाहर निकलना आवश्यक है। पंन्यासश्री ने जीवों के चार प्रकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनमें से तीन प्रकार के जीव अपनी श्रद्धा और पुरुषार्थ के बल पर भ्रमणा से बाहर निकल सकते हैं।

उन्होंने मोम के समान जीव का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अग्नि का स्पर्श होते ही मोम तुरंत पिघल जाता है, वैसे ही जिनके हृदय में सच्ची श्रद्धा होती है, उनके जीवन में धर्म का स्पर्श होते ही परिवर्तन आ जाता है। उन्होंने आत्ममंथन करने का आह्वान करते हुए कहा कि क्या हमारा जीवन वास्तव में मोम जैसा है? भगवान की पूजा और आराधना के बिना जीवन व्यर्थ है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, धर्म से जुड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा वही है, जो जीवन को पाप से दूर कर सन्मार्ग की ओर ले जाए।

पंन्यासश्री ने सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि चातुर्मास आत्मशुद्धि, आराधना और आत्मपरिवर्तन का अनुपम अवसर है। यदि जीवन में कभी कोई गलत अनुभव या भूल हुई हो तो उससे सीख लेकर स्वयं को सुधारने का संकल्प लें। चातुर्मास के दौरान अधिकाधिक आराधना करें, जिनवाणी के प्रति श्रद्धा दृढ़ करें तथा विराधना से बचते हुए आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों।

एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने मानवाधिकार केंद्र का उद्घाटन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने एसआरएम स्कूल ऑफ लॉ में मानवाधिकार अध्ययन केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून एवं शरणार्थी कानून केंद्र का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य उन्नत अनुसंधान, नीतिगत संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नए रास्ते खोलना है न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियन और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एआरएल सुंदरेशन ने एसआरएम स्कूल ऑफ लॉ,द्वारा आयोजित दीक्षांत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।अपने मुख्य अतिथिय भाषण में न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियन ने कहा कि छात्रों को ईमानदारी, दृढ़ता और आजीवन सीखने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ विधि पेशे में प्रवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों को कड़ी मेहनत और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। यद्यपि कानूनी ज्ञान सिखाया जा सकता है, लेकिन नैतिक आचरण, करुणा, विश्लेषणात्मक सोच और भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे गुण ही असाधारण वकीलों को परिभाषित करते हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुंदरेशन ने विधि पेशे से जुड़ी अनेक जिम्मेदारियों के बारे में बात की। उन्होंने अनुशासन, सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को नैतिक मूल्यों पर आधारित करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

धन सुविधा देता है मगर जीवन में सुरक्षा पुण्य ही दे सकता है : कपिल मुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहाँ मणिक्कम स्ट्रीट स्थित लक्ष्मी महल में चातुर्मासार्थ विराजित श्री कपिल मुनि जी म. सा. के चातुर्मासिक ओजस्वी प्रवचन माला का सोमवार से पंच परमेष्ठी स्तुति व तीर्थंकर भगवान के उत्कीर्तन से आगाज हुआ। इस मौके पर पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने उदबोधन में कहा कि इस संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है-शरीर, परिवार, धन, प्रतिष्ठा, अवसर यह सब संयोग है। और यह संयोग भी यूँ ही नहीं मिला, यह हमारे पूर्व संचित पुण्यों का प्रतिफल है। किंतु एक बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि योग का मिलना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन है उस योग का सही समय पर सदुपयोग करना। जीवन में जो भी मिला है, वह स्थायी नहीं है। मिला हुआ वास्तव में उसी को कहते हैं, जो एक दिन हमसे छिन जाने वाला है। संसार की प्रत्येक वस्तु की एक एक्सपायरी डेट निश्चित है। धन, यौवन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध और स्वयं यह शरीर भी सबका एक निश्चित समय है। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि उनके समाप्त होने से पहले उनका श्रेष्ठ उपयोग कर लिया जाए।

मनुष्य जीवन के पाँच महान उपकारियों में सबसे प्रमुख है-शरीर। यही शरीर धर्म का साधन है, यही साधना का माध्यम है और यही मोक्षमार्ग की पहली सीढ़ी है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन एकाग्र नहीं होगा, और जब मन ही एकाग्र नहीं होगा तो साधना कैसे सफल होगी? इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए जो शरीर की तंदुरुस्ती को नष्ट करे। असंयमित खान-पान, अनियमित दिनचर्या, क्रोध, तनाव, व्यसन और प्रमाद-ये केवल शरीर के ही नहीं, साधना के भी शत्रु हैं। स्वस्थ शरीर केवल चिकित्सा से नहीं, संयमित जीवनशैली, सात्त्विक आहार, नियमित दिनचर्या और पुण्यमय जीवन से प्राप्त होता है। जब कोई हमारा हालचाल पूछता है तो सहज ही उत्तर निकलता है- ऑल इज वेल। परंतु वास्तव में -ऑल इज वेल तभी कहा जा सकता है जब शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो और आत्मा संतुष्ट हो। यदि शरीर रोगग्रस्त है तो बाहरी वैभव भी आनंद नहीं दे सकता।

गुरुदेव ने कहा कि आज मनुष्य धन कमाने के लिए दिन-रात एक कर देता है। समय, श्रम, बुद्धि और सामर्थ्य का अधिकांश भाग संपत्ति अर्जित करने में लगा देता है। किंतु यदि उतना ही श्रम पुण्य कमाने में लगाया जाए-सेवा, दान, संयम, स्वाध्याय, तप, करुणा और धर्माराधना में लगाया जाए-तो जीवन की दिशा ही बदल सकती है। धन जीवन को सुविधाएँ दे सकता है, परंतु पुण्य जीवन को सुरक्षा देता है। धन बाहरी सुख देता है, जबकि पुण्य भीतर की शांति और संतोष का स्रोत बनता है। चातुर्मास रूपी संयोग का लाभ उठाकर जीवन को पुण्यमय और गुण वैभव से समृद्ध बनाएं। चातुर्मास समिति के चेयरमैन आनंदमल छल्लाणी ने बताया कि लक्ष्मी महल में 28 जुलाई से चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन सुबह प्रवचन दोपहर में ज्ञानार्जन और सूर्यास्त से प्रतिक्रमण व रात्रि में धर्मचर्चासत्र आदि धार्मिक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होंगे। धर्मसभा का संचालन चातुर्मास समिति के मंत्री शांतिलाल गुगलिया ने किया।

संगीत प्रतियोगिता में अंबत्तूर, वेलचेरी और तिरुवल्लुर की टीमें बनीं विजेता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। दक्षिण भारत जैन स्वाध्याय संघ एवं श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन संघ, साहुकारपेट के संयुक्त तत्वावधान में 26 जुलाई को साहुकारपेट स्थित जैन भवन में संगीत अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें चेन्नई महानगर, उपनगर और आसपास के नगरों की इक्कीस टीमों ने भाग लिया। तीर्थंकर भगवान के नाम से हर टीम में चार-चार सदस्य रहे। जयतिलक मुनि के मंगलपाठ से शुरू हुए कार्यक्रम में विमल सांखला मुख्य अतिथि थे।

जैन संघ के अध्यक्ष डॉ. संजय पींचा ने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि उन्होंने स्वाध्याय संघ से बहुत सीखा है। स्वाध्याय संघ के अध्यक्ष लाभचंद खारीवाल ने हर प्रतिभागी टीम को स्वाध्यायी तैयार करने की प्रेरणा दी। मंत्री विजया कोटेचा ने कहा कि संगीत ताप और संताप का हरण कर लेता है। यह हमारे संस्कार और संस्कृति को जीवित रखता है। बड़े उपदेश से जो बात नहीं हो पाती, वह संगीत की स्वर लहरियों से हो जाती है। साहित्यकार डॉ. दिलीप धींग ने इस अभिनव आयोजन की सराहना की।

तीन घंटे तक चले कार्यक्रम में अंबत्तूर, वेलचेरी और तिरुवल्लुर की टीम विजेता बनीं। प्रतियोगिता की विशेष बात यह रही कि हिंदी के गीतों को तुरंत ही राजस्थानी भाषा में बदलकर गाकर मायड़ भाषा को गौरवान्वित किया। चित्र देखकर संस्कृत के भक्तामर स्तोत्र का संबंधित श्लोक गाना भी स्पर्धा का हिस्सा रहा। सभी टीमों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सबको सांत्वना पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में पृथ्वीराज बागरेचा, जयंतीलाल कावड़िया, महावीरचंद खाबिया, सुरेन्द्र कोठारी, ऋषभ घोड़ावत, तरुण-दीपेश खारीवाल सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे।

फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को 'संस्कृति कलाश्री अवार्ड' से सम्मानित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। संस्कृति कल्चरल फाउंडेशन द्वारा चेन्नई के प्रतिष्ठित म्यूज़िक अकादमी प्रांगण में आयोजित भव्य समारोह में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री को 'संस्कृति कलाश्री अवार्ड' से सम्मानित किया गया। समारोह में शहर के अनेक प्रतिष्ठित एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मीनाक्षी शेषाद्री, प्रथम महिला शशि बागड़ी, ऊर्वी सिंघवी तथा वंदना जैन द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

संस्था के अध्यक्ष गिरी बागड़ी ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का हार्दिक स्वागत करते हुए बताया कि संस्कृति कल्चरल फाउंडेशन पिछले 26 वर्षों से भारतीय कला, संस्कृति एवं संस्कारों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निरंतर कार्यरत है। फाउंडेशन के चेयरमैन के. एल. जैन ने अपने संबोधन में कहा कि कला और संस्कृति के संरक्षण एवं विकास में कद्रदानों का अमूल्य योगदान होता है। उन्होंने सभी सहयोगियों एवं सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संस्था के समर्पित कोषाध्यक्ष विनोद कोठारी को 'संस्कृति के मेस्सी' की विशेष उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि श्री कोठारी के प्रयासों से संस्था को 100 नए कद्रदान सदस्य प्राप्त हुए। उन्होंने कार्यक्रम के शीर्षक 'प्यार करने वाले' को समाज में प्रेम, सौहार्द और विश्वास का संदेश देने वाला बताया।

मुख्य अतिथि अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने सभी प्रायोजकों को अपने करकमलों से स्मृति-चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के शीर्षक प्रायोजक, डायमंड प्रायोजक, गोल्ड प्रायोजक सिल्वर प्रायोजक एवं रिहर्सल स्थल प्रायोजक को स्मृति-चिह्न भेंट किए गए।

'प्यार करने वाले' कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृति के चयनित कलाकारों ने सदाबहार फिल्मी गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों से वातावरण को संगीतमय बना दिया। महिलाओं एवं बच्चों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और खूब सराहना प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन रीटा चोरड़िया ने किया। मुख्य अतिथि से सीधी बातचीत धनपत जैन ने की।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

विप्र क्रिकेट टूर्नामेंट

विप्र स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित विप्र प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे रविवार को कुल छ मैच आयोजित किए गए। विप्र स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन चैन राज सेवग ने बताया कि रविवार के सारे मैच व्हाइट जर्सी ग्राउंड पर खेले गए। आज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के पुरस्कार स्व राम नारायण गौड़, अनिल कुमार गौड़, शर्मा प्लाई एंड लेमिनेट्स द्वारा प्रायोजित किए गए थे।

जीतो साउथ लेडीज़ विंग ने 'जीरावला तीर्थ' की आध्यात्मिक यात्रा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गेनाइजेशन(जीतो) साउथ द्वारा सेवा वर्टिकल के अंतर्गत 'दिव्यता' नामक कार्यक्रम में शहर के जीरावला तीर्थ की आध्यात्मिक यात्रा की।

विंग की साउथ की चेयरपर्सन बबीता रायसोनी ने सभी सदस्याओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दिव्यता' का मुख्य उद्देश्य सदस्याओं को एक-दूसरे के और करीब लाना, आपसी रिश्तों को मजबूत करना, नए संबंध एवं नेटवर्किंग विकसित करना और साथ ही पवित्र चौमासे की शुरुआत भगवान पार्श्वनाथ के आशीर्वाद से करना है।

साउथ की संयोजिका चंद्रा जैन, सहसंयोजिका अंगिका बाफना ने अपने विचार व्यक्त किए। यात्रा का मुख्य आध्यात्मिक आकर्षण जय जीरावला पार्श्वनाथ मंदिर में आयोजित स्नात्र पूजा रही। प्रभु दर्शन के अलावा विभिन्न रोचक एवं मनोरंजक खेलों का भी आयोजन किया गया।

भोग के समान अधर्म नहीं, त्याग ही धर्म का वास्तविक स्वरूप : जयतिलक मुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। पआचार्य भगवंत 1008 श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब एवं श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के शिष्य, जैन भवन में विराजित पूज्य गुरुदेव श्री जयतिलक मुनि जी म.सा. ने सोमवार को धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भोग के समान अधर्म नहीं तथा त्याग के समान धर्म नहीं। उन्होंने कहा कि जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है और जब तक जीव की आसक्ति भोग-उपभोग में बनी रहती है, तब तक आत्मकल्याण एवं मोक्ष का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट भी भोग-विलास का त्याग कर दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही मोक्षमार्ग की ओर अग्रसर होते हैं।फ

इच्छा ही संसार-भ्रमण का मूल कारण है तथा इन्द्रियों और मन पर विजय प्राप्त करने वाला जीव ही आत्मोन्नति कर सकता है। भोग अशान्ति को बढ़ाता है, जबकि त्याग शान्ति एवं शुभ नामकर्म का कारण बनता है। यह शरीर नश्वर एवं पुद्गल स्वरूप है, अतः इसकी आसक्ति छोड़कर आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म, तप, त्याग एवं जिनवाणी श्रवण को जीवन का आधार बनाना चाहिए।

पूज्य गुरुदेव ने चातुर्मास के चार पावन महीनों में अधिक से अधिक धर्म आराधना, स्वाध्याय, तप एवं जिनवाणी श्रवण करने का आह्वान करते हुए कहा कि यही आत्मा को हल्का कर मोक्षमार्ग की ओर अग्रसर करने का श्रेष्ठ अवसर है। धर्मसभा का संचालन करते हुए एस.एस. जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन संघ,साहूकार पेठ के अध्यक्ष डॉ. संजय पिंचा ने बताया कि 29 जुलाई से जैन भवन परिसर में पूज्य गुरुदेव के सान्निध्य में सिद्धि तप का शुभारम्भ एकासना से होगा। इसी दिन चातुर्मास की विविध धार्मिक आराधनाओं एवं जीवदया कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सभी श्रावक-श्राविकाओं से अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्मलाभ लेने का आग्रह किया।

संकल्प ही आत्मा को परमात्मा बनाता है : राष्ट्रसंत कमलमुनि

मैसूरु/दक्षिण भारत। शहर के स्थानकवासी जैन संघ हल्लदकेरी स्थित स्थानक भवन से राष्ट्रसंत कमल मुनिजी कमलेश ने अपने प्रवचन में कहा कि साधना की आत्मरूपी भूमि में संकल्प के बीज का बीजारोपण व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र के जब तक नहीं करता है, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मा की अनंत शक्ति को जागृत करके संकल्प के माध्यम से आत्मा की शक्ति केंद्रित होती है, उससे ऊर्जा का संचार होता है।

संकल्प ही आत्म साधना की यात्रा के लिए मिल का पत्थर साबित होता है। जितना फौलादी संकल्प होगा उतनी ही सफलता शीघ्र उसके चरण संकल्प शक्ति ही अमृत के समान है। प्रवचन सभा में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उपस्थित थे। संचालन बुधमल बाघमार ने किया ।

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.